



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-01022024-251708
CG-MP-E-01022024-251708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945

No. 65]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

अमरकंटक, 29 जनवरी, 2024

पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया विनियम, 2022

[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया)
विनियम 2022 के अनुरूप]

क्रमांक: आई.जी.एन.टी.यू./आरओ/2024/88.—

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन.—

- 1.1. 'डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी' की उपाधि को लघु रूप में आगे से 'पी-एच.डी.' लिखा जाएगा।
- 1.2. इन विनियमों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (आगे से इ.गां.रा.जजा.विवि., अमरकंटक) की पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया विनियम 2022 कहा जाएगा।
- 1.3. यह विनियम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक तथा इसके क्षेत्रीय परिसरों (आगे से क्षेत्र.प.) द्वारा संचालित किए जा रहे समस्त अध्ययन शाखाओं / विषयों पर लागू होंगे।
- 1.4. यह विनियम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए विगत समस्त पी-एच.डी. विनियम, जब तक कि इस विषय में अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो, इन विनियमों के जारी होने की तिथि से अमान्य होंगे।

1.5. इन विनियमों (अर्थात् यूजीसी / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पी-एच.डी. विनियम, 2022) की अधिसूचना की तिथि तक, 11 जुलाई, 2009 या उसके पश्चात् पी-एच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकृत शोधार्थियों को उपाधि प्रदान करना यूजीसी विनियम, 2009 के प्रावधानों (एम.फिल. / पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) या यूजीसी विनियम, 2016 (एम.फिल. / पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक पी-एच.डी. विनियम, 2016, जैसा भी प्रकरण हो, द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पहले से पंजीकृत तथा पी-एच.डी. कर रहे शोधार्थियों को उपाधि प्रदान करना इन विनियमों (अर्थात् यूजीसी / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पी-एच.डी. विनियम 2022) या यूजीसी विनियम, 2016 (एम.फिल. / पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक पी-एच.डी. विनियम, 2016 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। (अनुच्छेद 16: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

2. परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के 3) से है;

ख) "अनुबंधक संकाय" का अर्थ अंशकालिक या आकस्मिक शिक्षक/कर्मचारी से है, न कि एक पूर्णकालिक संकाय सदस्य से जो कि किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया हो;

ग) "संचित ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर्स में एक विद्यार्थी के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर्स में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट पॉइंट का अनुपात तथा सभी सेमेस्टर्स में समस्त पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट के योग का अनुपात है। इसे दशमलव के दो स्थानों तक व्यक्त किया जाता है;

घ) "क्रेडिट" का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन-क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह एक-घंटे के तीन व्याख्यान, जिसमें प्रत्येक एक-घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिट के रूप में गिना जा सकता है;

च) "विश्वविद्यालय" का अर्थ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक से है;

छ) "क्षेत्रीय परिसर" का अर्थ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के विधि सम्मत स्थापित परिसरों से है;

ज) "महाविद्यालय" का अर्थ उच्चतर शिक्षण और / या शोध में संलग्न एक संस्था से है, जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है या इससे संबद्ध है;

झ) "आयोग" का अर्थ यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

ञ) "पाठ्यक्रम" का अर्थ उन विशिष्ट इकाइयों में से एक है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को शामिल करती है;

ट) "कोर्स वर्क" का अर्थ है विद्यालय / विभाग / केंद्र द्वारा पी-एच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थियों के अध्ययन हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम;

ठ) "उपाधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा 22 (3) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि;

ड) "बाह्य परीक्षक" का अर्थ एक शिक्षाविद् / अनुसंधानकर्ता से है जो उस उच्च शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा न हो जहां पी-एच.डी. अध्येता ने पी-एच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है;

ढ) "विदेशी शैक्षणिक संस्थान" का अभिप्राय है - (i) उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता हो और (ii) जो पारंपरिक मुखाभिमुख तरीके के माध्यम से उपाधि प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम/कार्यक्रमों की पेशकश करता हो, ना कि ऑनलाइन, मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से;

ण) "ग्रेड पॉइंट्स" का अर्थ 10-बिंदु पैमाने पर प्रत्येक अक्षर ग्रेड को आवंटित संख्यात्मक भार से है;

त) "गाइड / शोध पर्यवेक्षक" का अर्थ है उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिक्षाविद् / शोधकर्ता जो पी-एच.डी. शोधार्थी और उसके शोध की निगरानी करे;

थ) "उच्चतर शिक्षण संस्थान" का अर्थ इन विनियमों के विनियम 1 के खंड 2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थान से है;

द) "अंतर्विषयक शोध" का अर्थ दो या अधिक शैक्षणिक विषयों में पी-एच.डी. अध्येता द्वारा किए गए शोध से है;

ध) "मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम" का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम 2020 के अंतर्गत परिभाषित है;

न) "ऑनलाइन माध्यम" का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम 2020 के अंतर्गत परिभाषित है;

प) "साहित्यिक चोरी" का अर्थ है किसी और के कार्य या विचार को स्वयं के मूल कार्य के रूप में प्रकाशित कराना;

फ) "कार्यक्रम" का अर्थ अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपाधि हेतु अपनाया जाने वाला उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम है;

ब) "विवरण पुस्तिका" का अर्थ है कोई भी प्रकाशन, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा, उच्चतर शिक्षण संस्थान और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को (ऐसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक हों) निष्पक्ष एवं पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया हो;

भ) "शोध प्रस्ताव" का अर्थ है प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देने वाला एक संक्षिप्त आलेख, जो पी-एच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पी-एच.डी. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम में परिभाषित और इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं, उनका अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में दिया जाएगा।

(अनुच्छेद 2: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

3. विज्ञापन, सीटों की संख्या एवं प्रवेश सूचना

3.1 विश्वविद्यालय शोधार्थियों के सूचनार्थ न्यूनतम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा, के साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवश्यक अर्हता, प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय / धारा-वार वितरण, प्रवेश हेतु मानदण्ड, प्रवेश हेतु प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सूची, उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों की संख्या एवं विशेषज्ञता सहित आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, इत्यादि को समाहित करते हुए एक विस्तृत विज्ञापन देगा।

3.2 संबंधित विभागीय शोध समितियों (आगे से वि.शो.स.) की अनुशंसाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद (आगे से अ. प.) विश्वविद्यालय एवं क्षेत्र.प. के विभिन्न विभागों में प्रवेश तथा विज्ञापित की जाने वाली सीटों की संख्या की वार्षिक अनुशंसा करेगी। यूजीसी विनियम 2022 के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर क्षेत्र.प. पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश दे सकते हैं।

3.3 आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.igntu.ac.in) पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

3.4 अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.जजा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.)-नॉन-क्रीमी लेयर, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू.एस.) तथा अन्य श्रेणियों के शोधार्थियों की सीटों का आरक्षण समय-समय पर जारी भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा।

3.5 योग्य शोधार्थियों की संख्या कम होने पर अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व./ई. डब्ल्यू.एस. श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आनुपातिक रूप से कम की जा सकती हैं। अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व./ई. डब्ल्यू.एस. शोधार्थियों हेतु आरक्षित रिक्त सीटें, यदि कोई हों, तो उन्हें भारत सरकार के नियमों के अनुसार भरा जाएगा।

3.6 प्रत्येक अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व./ई. डब्ल्यू.एस. शोधार्थी को अधिसूचित व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करनी होगी, जिसमें उल्लेख किया गया हो कि शोधार्थी भारत सरकार के प्रारूप के अनुसार अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) समुदाय/ई. डब्ल्यू.एस. से संबंधित है तथा नियम जो स्पष्ट रूप से बताते हैं: (क) शोधार्थी का नाम और उसकी जाति/जनजाति (ख) वह किस आरक्षित श्रेणी से संबंधित है (ग) उसके सामान्य निवास का जिला एवं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तथा (घ) भारत सरकार की उचित अनुसूची जिसके अंतर्गत उसकी

जाति/जनजाति अनुमोदित है। अ.पि.व. प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि शोधार्थी क्रीमी लेयर श्रेणी से संबन्धित नहीं है।

4. पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड

4.1 निम्नलिखित शोधार्थी पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं:

4.2 वह शोधार्थी जिन्होंने निम्नलिखित कार्यक्रम पूर्ण किया है:

4.2 (i) 4-वर्षीय / 8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1-वर्ष / 2-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3-वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय / 4-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है; अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55% अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

4.2 (ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) / दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5% अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

4.2 (iii) बशर्ते, 4-वर्षीय / 8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय-समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5% अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

4.2 (iv) एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त शोधार्थी पी-एच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

(अनुच्छेद 3: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

5. प्रवेश की प्रक्रिया

5.1 विश्वविद्यालय में पी-एच.डी. में प्रवेश यूजीसी तथा अन्य संबद्ध वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों/मानदण्डों तथा समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्डों पर आधारित होगा।

5.2 पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा:

5.2 (i) वह शोधार्थी जिन्होंने यूजीसी-नेट/यूजीसी-सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी/जीपीएटी तथा समरूपी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/विद्यार्थीवृत्ति हेतु अर्हता प्राप्त की है।

अथवा

5.2 (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। इसके पाठ्यक्रम में 50% शोध पद्धति तथा 50% विषय-विशिष्ट समाहित होंगे।

5.2 (iii) शोध प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त विद्यार्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के पात्र होंगे।

5.2 (iv) सरकार द्वारा समय-समय पर/आयोग के निर्णय के अनुसार (अर्थात् यूजीसी या उसके क्रमानुयायी) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग/ई.डब्ल्यू.एस. तथा अन्य श्रेणियों के शोधार्थियों के लिए 5% अंक या इसके समकक्ष श्रेणी की छूट दी जा सकती है।

5.2 (v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पी-एच.डी. सीटों की उपलब्ध संख्या के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले पात्र विद्यार्थियों की संख्या तय करेगा।

5.2 (vi) वरीयता सूची निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा के लिए 70% तथा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30% की भारिता दी जाएगी।

विश्वविद्यालय:

5.3.(i) प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/शिक्षण-वार वितरण, प्रवेश हेतु मानदण्ड, प्रवेश की प्रक्रिया तथा शोधार्थियों हेतु अन्य समस्त प्रासंगिक जानकारी निर्दिष्ट करते हुए संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरणिका अग्रिम में अधिसूचित करेगा (अनुच्छेद 3.1 का संदर्भ लें);

5.3 (ii) राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय आरक्षण नीति, जहां लागू हो, का पालन करेगा (अनुच्छेद 3.4 एवं 3.5 का संदर्भ लें)।

5.4 (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पी-एच.डी. पर्यवेक्षकों की एक सूची अनुरक्षित रखेगा (पर्यवेक्षक का नाम, उनका पदनाम एवं विभाग/विद्यालय/केंद्र निर्दिष्ट करते हुए), साथ ही उनके अधीन पी-एच.डी. अध्येताओं के विवरण (पंजीकृत पी-एच.डी. अध्येता का नाम, उनके शोध का शीर्षक तथा प्रवेश की तिथि निर्दिष्ट करते हुए) उपलब्ध कराएगा। इस विवरण को प्रत्येक अकादमिक वर्ष में अद्यतित किया जाएगा।

(अनुच्छेद 5: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

6. शोधार्थियों का वर्गीकरण

6.1 विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त शोधार्थी को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा:

6.1 (i) पूर्णकालिक शोधार्थी

अनुच्छेद 4.2.1-4.2.4 में वर्णित पात्रता मानदण्ड के आधार पर पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त शोधार्थी को पूर्णकालिक शोधार्थी कहा जाएगा।

6.1 (ii) आंतरिक पूर्णकालिक शोधार्थी

अनुच्छेद 4.2.1-4.2.4 में वर्णित पात्रता मानदण्ड के आधार पर पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त शोधार्थी को आंतरिक पूर्णकालिक शोधार्थी कहा जाएगा।

क. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय एवं इसके क्षेत्रीय परिसरों में कार्यरत नियमित शिक्षक को आंतरिक शोधार्थी के रूप में नामित किया जाएगा। इस हेतु उन्हें नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे शोधार्थियों को कोर्स वर्क पूर्ण करने के लिए छह माह का अध्ययन अवकाश लेना अनिवार्य होगा।

ख. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय एवं उसके क्षेत्रीय परिसरों में कार्यरत गैर-शैक्षणिक नियमित कर्मचारी को आंतरिक शोधार्थी के रूप में नामित किया जाएगा। इस हेतु उन्हें नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे शोधार्थियों को कोर्स वर्क पूर्ण करने के लिए छह माह का अध्ययन अवकाश लेना अनिवार्य होगा। ऐसे शोधार्थियों को पी-एच.डी. कार्यक्रम हेतु शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा ऊपर उल्लिखित 'छूट प्राप्त श्रेणी' के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करनी होगी।

6.1 (iii) बाह्य पूर्णकालिक शोधार्थी

ऐसे संस्थान जिन्होंने विश्वविद्यालय से समझौता ज्ञापन कर रखा है, या एक शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर रखी है या गैर-उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों जिनके साथ विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन कर रखा है, में पी-एच.डी. कर रहे शोधार्थी को बाह्य पूर्णकालिक शोधार्थी के रूप में कार्य करने की अनुमति भी दी जाएगी, जो इन विनियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का विधिवत अनुपालन करते हुए अपने मूल संगठन में अपनी पी-एच.डी. हेतु कार्य करेंगे। ऐसे शोधार्थी

अपना कोर्स वर्क अपने मूल संस्थानों में पूर्ण कर सकते हैं, बशर्ते कोर्स वर्क इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, अन्यथा, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कोर्स वर्क में भाग लेने के लिए अपने मूल संस्थान से छह (06) माह का अध्ययन अवकाश लेकर इसे पूर्ण करना होगा। तथापि, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त समस्त शोधार्थियों को केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोर्स वर्क परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी।

6.1 (iii) यदि बाह्य पूर्णकालिक शोधार्थी अपने संबन्धित संस्थानों से कोर्स वर्क कक्षाओं में भाग लेता है, तो उसे संस्थान/संगठन के निदेशक/कुलपति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित हो कि उनका कोर्स वर्क विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के समकक्ष है।

6.1.4 अंशकालिक पी-एच.डी.

6.1.4 (i) विश्वविद्यालय द्वारा अंशकालिक पी-एच.डी. की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते शोधार्थी इन विनियमों में निर्धारित सभी शर्तें पूरी करते हों।

6.1.4 (ii) ऐसे शोधार्थियों को अपने मूल संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जमा करना होगा जहां शोधार्थी कार्यरत है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि:

क) शोधार्थी को अंशकालिक आधार पर पढ़ाई करने की अनुमति है।

ख) उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध हेतु पर्याप्त समय की अनुमति देते हैं।

ग) आवश्यकतानुसार उन्हें कोर्स वर्क पूर्ण करने के लिए कार्य से मुक्त किया जाएगा।

6.1.5 अंशकालिक शोधार्थी को कोर्स वर्क पूर्ण करने के लिए छह (06) माह का अवकाश लेना अनिवार्य होगा (अनुच्छेद 13: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)। अनुच्छेद 4 के अतिरिक्त, अंशकालिक पी-एच.डी. में प्रवेश हेतु पात्रता परिशिष्ट-1 में उल्लिखित है।

6.1.6 विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पी-एच.डी. के लिए संबद्ध वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया तय कर सकता है। (अनुच्छेद 7: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)।

6.1.7 प्रवेश में सफल शोधार्थियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा तथा निर्धारित समय के भीतर अपने प्रवेश से संबन्धित अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।

6.1.8 प्रवेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर विभाग/स्कूल/केंद्र अध्यक्ष/समन्वयक विश्वविद्यालय के शोध प्रकोष्ठ/पी-एच.डी. अनुभाग को प्रवेश प्राप्त शोधार्थियों की पूर्ण सूची के साथ आवश्यक विवरण भेजेंगे जिसकी एक प्रति संबन्धित अधिष्ठाता को भी भेजी जाएगी।

6.1.9 शोध अवधि के दौरान किसी नियमित पी-एच.डी. शोधार्थी को अन्य नियमित और सवैतनिक नौकरी/समनुदेशन (अनुच्छेद 6.1.2 एवं 6.1.4 के अंतर्गत पंजीकरण के अतिरिक्त) की अनुमति नहीं दी जाएगी, संबन्धित वि.शो.स. द्वारा स्वीकृत शोध अध्येतावृत्तियां, शोध सहायकता/बाह्य वित्तपोषित शोध परियोजना समनुदेशन इसके अपवाद रहेंगे बशर्ते वह शोधार्थी के शोध कार्य के लिए हानिकारक न हों।

6.1.10 किसी पी-एच.डी. अध्येता को किसी अन्य डिग्री पाठ्यक्रम से जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि उन्हें शो.स.स. की अनुशंसा पर संबन्धित वि.शो.स. द्वारा अंशकालिक डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम(मों) से जुड़ने का अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वे अध्येता के शोध कार्यक्रम के लिए हानिकारक न हों। (निरसित)

6.1.11 शिक्षण से पृथक्, समस्त पी-एच.डी. शोधार्थियों से अपनी डॉक्टरल अवधि के दौरान अपने चुने गए पी-एच.डी. विषय से संबन्धित शिक्षण/शिक्षा/अध्यापन/लेखन में प्रशिक्षण देना अपेक्षित होगा। पी-एच.डी. शोधार्थियों को अनुशिक्षण या प्रयोगशाला कार्य एवं मूल्यांकन आयोजित करने हेतु शिक्षण/शोध सहायक के प्रति सप्ताह 4-6 घंटे भी समनुदेशित किए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 9: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

7. शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक तथा अनुमेय पी-एच.डी. शोधार्थियों की संख्या

विश्वविद्यालय द्वारा पात्र शोध पर्यवेक्षकों/सह-पर्यवेक्षकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसे वि.शो.स. द्वारा अनुशंसित तथा विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7.1 शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक हेतु पात्रता

7.1 (i) विश्वविद्यालय (क्षे.प. समेत) सेवा में स्थायी रूप से कार्यरत एवं शोध पर्यवेक्षक के रूप में अनुमोदित प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर जिन्होंने स्वयं पी-एच.डी. कर रखी हो तथा पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में न्यूनतम पांच शोधपत्र/आलेख प्रकाशित किया हो।

7.1 (ii) विश्वविद्यालय (क्षे.प. समेत) सेवा में स्थायी रूप से कार्यरत एवं शोध पर्यवेक्षक के रूप में अनुमोदित असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने स्वयं पी-एच.डी. कर रखी हो तथा पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में न्यूनतम तीन शोधपत्र/आलेख प्रकाशित किया हो।

ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोध अध्येताओं का पर्यवेक्षण नहीं कर पाएंगे तथा केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

7.1 (iii) **निरसन:** अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (क्षे.प. समेत) के असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यवेक्षक एवं सह-पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

संशोधित: परिवीक्षा अवधि के दौरान भी पात्र स्थायी संकाय सदस्य पी-एच.डी. शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकेंगे (यूजीसी सूचना सं.एफ. 9-1/2020 (पीएस/विविध) दिनांकित 06/03/2023)

7.1 (iv) ऐसे क्षेत्रों/विषयों में जहां समकक्ष-समीक्षित या संदर्भित पत्रिकाओं की संख्या शून्य या सीमित हो, विश्वविद्यालय लिखित कारणों के साथ शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता हेतु उक्त शर्त में छूट दे सकता है।

7.1 (v) केंद्र सरकार/राज्य सरकार शोध संस्थानों में कार्यरत पी-एच.डी. शोधार्थी जिनकी उपाधियां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएंगी, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य हैं, को पर्यवेक्षकों (अर्थात् बाह्य पर्यवेक्षक) के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह अनुच्छेद 7.1.1-7.1.2 में वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों।

(अनुच्छेद 6: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

7.1 (vi) अनुबंधक संकाय शोध पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य नहीं करेंगे, केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर करेंगे।

7.1 (vii) विश्वविद्यालय अंतर्विषयक एवं अत्याधुनिक शोध को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासरत रहेगा। ऐसे शोधकार्य में अपेक्षानुसार विभाग/स्कूल/केंद्र/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर से किसी सह-पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

7.1 (viii) विवाह या किसी अन्य कारण से महिला पी-एच.डी. शोधार्थी के स्थानांतरण के संदर्भ में, शोध आंकड़ों को उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में स्थानांतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी स्थानांतरित होना चाहता है, बशर्ते इन विनियमों में अन्य सभी शर्तों का पालन किया जाए, तथा उक्त शोध कार्य तथा आंकड़े किसी निधीयन अभिकरण द्वारा मूल संस्थान/पर्यवेक्षक को स्वीकृत परियोजना से संबन्धित नहीं हो। तथापि, ऐसे शोधार्थी को पहले से किए गए शोध के अंश हेतु मूल संस्थान तथा पर्यवेक्षक को उचित श्रेय देना होगा।

7.1 (ix) ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति में तीन (03) वर्ष या इससे कम का समय बचा हो को नये शोधार्थियों को अपने पर्यवेक्षण के अधीन रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, ऐसे संकाय सदस्य पूर्व पंजीकृत पी-एच.डी. शोधार्थी का पर्यवेक्षण अपनी सेवानिवृत्ति तक जारी रख सकते हैं तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सह-पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, उसके बाद नहीं।

(अनुच्छेद 6: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

7.1 (x) आंतरिक एवं बाह्य सह-पर्यवेक्षक/बाह्य पर्यवेक्षक दोनों को संबन्धित शो.स.स. के अनुरोध तथा संबन्धित वि.शो.स. की संस्तुति के आधार पर ही नियुक्त किया जाएगा।

7.1 (xi) किसी भी शिक्षक को अपने रक्त संबन्धियों का पर्यवेक्षण/सह-पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.2 शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण एवं नये पर्यवेक्षक की नियुक्ति:

7.2 (i) चयनित शोधार्थी हेतु शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण संबन्धित वि.शो.स. द्वारा इन नियमों में अन्यत्र निर्दिष्ट शोध पर्यवेक्षक अध्येताओं की अधिकतम संख्या, पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता तथा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के समय उनके द्वारा बताए गए शोधार्थियों के शोध हितों के आधार पर तय किया जाएगा।

7.2 (ii) शोधार्थी की शोध रुचि को ध्यान में रखते हुए, संबन्धित वि.शो.स. शोधार्थी के शोध कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक एवं बाह्य सह-पर्यवेक्षक (बाह्य पूर्णकालिक शोधार्थी के प्रकरण में अनिवार्य), बाह्य पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे; पर्यवेक्षक की सहायता के लिए इन विनियम(मों) के संबन्धित प्रावधानों के अनुसार गठित शोध सलाहकार समिति (शो.स.स.) को भी अधिसूचित करेंगे।

7.2 (iii) एक ही विभाग या एक ही संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों से सह-पर्यवेक्षकों को संबन्धित वि.शो.स. की अनुशंसा तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर शोध निर्देशन करने की अनुमति दी जा सकती है।

7.2 (iv) पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के निर्धारण के पश्चात, शोधार्थी को अपने शो.स.स. के माध्यम से स्कूल/केंद्र के विभागाध्यक्ष/समन्वयक को शोध के प्रस्तावित विषय को सूचित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। किसी बाह्य पूर्णकालिक शोधार्थी के लिए उपर्युक्त आवेदन के साथ वि.शो.स. या उस संस्थान के समकक्ष निकाय द्वारा अनुमोदित / प्रस्तावित बाह्य सह-पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक की सहमति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7.2 (v) ऐसे प्रकरण में जहां शोधार्थी का पर्यवेक्षक सहयोगी या संबद्ध विभागों (जैसा कि परिशिष्ट- II में निर्दिष्ट है) में नियुक्त किया जा चुका है तथा सह-पर्यवेक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अन्य विभाग से है, ऐसे शोधार्थी के पास नए पर्यवेक्षक के साथ वर्तमान विभाग में शोध करने के साथ, अपने पूर्व पर्यवेक्षक के साथ नए विभाग में स्थानांतरण का प्रावधान (पंजीकरण की तिथि से केवल एक वर्ष के भीतर) उपलब्ध होगा, बशर्ते कि शोधार्थी इसका विकल्प चुनता हो तथा संबन्धित विभाग की वि.शो.स. प्रस्तावित स्थानांतरण के लिए सहमत हो। स्थानांतरण के पश्चात शोधार्थी उस विभाग/संकाय के नियमों द्वारा शासित होगा जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है।

7.2 (vi) यदि किसी शोधार्थी का पर्यवेक्षक 12 माह से अधिक की अवधि हेतु अवकाश/ग्रहणाधिकार/प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसे संबन्धित वि.शो.स. से शोधार्थी के लिए एक सह-पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध करना होगा।

7.2 (vii) यदि कोई पर्यवेक्षक 12 माह से कम की अवधि हेतु अवकाश/ग्रहणाधिकार/प्रतिनियुक्ति पर जाता है, लेकिन बाद में अपने अवकाश/ग्रहणाधिकार/प्रतिनियुक्ति को 12 माह से अधिक के लिए बढ़ा देता है, तथा विद्यार्थी के लिए कोई सह-पर्यवेक्षक नहीं है, तो वह पर्यवेक्षक नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में संबन्धित वि.शो.स. शोधार्थी के लिए एक नए पर्यवेक्षक की नियुक्त करेगी।

7.2 (viii) यदि किसी शोधार्थी के पर्यवेक्षक की मृत्यु हो जाती है या उन्हें विश्वविद्यालय सेवा से प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो वह पर्यवेक्षक नहीं रहेगा। ऐसे प्रकरण में संबन्धित वि.शो.स. एक नया पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी।

7.2 (ix) ऐसे समस्त प्रकरणों में, जहां किसी शोधार्थी का वर्तमान पर्यवेक्षक किन्हीं कारणों से पर्यवेक्षक नहीं रह जाता है, संबन्धित वि.शो.स. एक नए पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी। यदि शोधार्थी के पास विश्वविद्यालय के किसी अन्य विभाग में सह-पर्यवेक्षक है, तो शोधार्थी उस विभाग में अपने स्थानांतरण का विकल्प चुन सकता है, तथा उसे दोनों वि.शो.स. की आपसी सहमति पर ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

7.2 (x) किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में संबन्धित वि.शो.स. के अध्यक्ष वि.शो.स. द्वारा नये पर्यवेक्षक की नियुक्ति तक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। इस तरह के पर्यवेक्षण की प्रकृति अस्थायी मानी जाएगी। यदि विभाग में पर्याप्त योग्य शिक्षक नहीं हैं, या कोई अन्य ठोस कारण है अथवा वि.शो.स. के अध्यक्ष एक वर्ष से अधिक समय तक अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों को जारी रखते हैं, तो उन्हें स्वतः ही शोधार्थी के पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर दिया जाएगा।

7.2 (xi) यदि शोधार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के विरुद्ध लिखित में यौन उत्पीड़न/शोषण से संबन्धित गंभीर शिकायत/आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में यूजीसी (एचईआईएस में महिला कर्मचारियों और विद्यार्थियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण) विनियम, 2015 के प्रावधान तथा उसके बाद के संशोधनों के अनुसार सख्त कार्यावाही की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में जांच की अवधि के दौरान संबन्धित विभाग/केंद्र/स्कूल के अध्यक्ष/समन्वयक अंतरिम पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। शिकायत प्राप्त होने की तिथि से छह (06) माह के भीतर ऐसी जांच पूर्ण करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा। यदि आरोप सही पाया जाता है तो संबन्धित वि.शो.स. शोधार्थी के लिए एक नया पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में शोधार्थी को मूल पर्यवेक्षक के निर्देशन में शोध कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त, आरोप मिथ्या पाए जाने की स्थिति में ऐसे शोधार्थी के विरुद्ध पंजीकरण रद्द करने सहित यथोचित आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

7.2 (xii) यदि पर्यवेक्षक ग्रहणाधिकार/प्रतिनियुक्ति पर जाता है तथा अपने शोधार्थी को नए संस्थान में स्थानांतरित करना चाहता है, तो ऐसा कोई प्रस्ताव शोधार्थी के पंजीकरण की तिथि (प्रथम शुल्क भुगतान तिथि) से केवल एक वर्ष के भीतर ही मान्य होगा।

7.2 (xiii) यदि पर्यवेक्षक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के किसी अन्य विभाग में पुनर्नियुक्त होता है, तो शोधार्थी मूल विभाग में शोध कार्य जारी रख सकता है जहां वह पंजीकृत था। ऐसे प्रकरण में, संबन्धित वि.शो.स. शोधार्थी के लिए एक नया पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। पूर्व-पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकता है।

7.3 किसी शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के अधीन शोधार्थियों की संख्या

7.3 (i) एक शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक जो एक समयावधि में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्रमशः अधिकतम आठ (08), छह (06), तथा चार (04) पी-एच.डी. शोधार्थियों का पर्यवेक्षण कर सकता है।

7.3 (ii) सह-पर्यवेक्षक के अधीन कार्य कर रहे पी-एच.डी. शोधार्थियों की संख्या को भी उनके विद्यार्थियों के अनुमेय कोटा में गिना जाएगा।

7.3 (iii) अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रकरण में प्रत्येक पर्यवेक्षक अनुच्छेद 7.3.1 में यथा निर्दिष्ट पी-एच.डी. शोधार्थियों की अनुमेय संख्या के अतिरिक्त दो अंतरराष्ट्रीय शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है।

(अनुच्छेद 6, 7 एवं 8: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

7.4 अंतर्विषयक शोध

7.4 (i) किसी शोधार्थी को अंतर्विषयक शोध करने की अनुमति दी जा सकती है। उसे उस संस्थान/विभाग/केंद्र/स्कूल के अलावा जहां से उसने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो, के अतिरिक्त, किसी अन्य विभाग/स्कूल/संकाय में प्रवेश/पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए उसने अपनी शोध समस्या की प्रकृति के आधार पर तथा संबन्धित वि.शो.स. की अनुशंसा प्राप्त की हो।

7.4 (ii) अंतर्विषयक क्षेत्र में शोध हेतु शोधार्थी के आवेदन पर इस तरह के कार्य के लिए उसकी सिद्ध क्षमता एवं योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

7.4 (iii) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के रूप में इंटरफेस विषय में विशेषज्ञता रख रहे ऐसे शिक्षकों की एक सूची तैयार करेगा।

8. कार्यक्रम की अवधि

8.1 प्रवेश की तिथि से कोर्स वर्क सहित पी-एच.डी. कार्यक्रम न्यूनतम तीन (03) वर्ष तथा अधिकतम छह (06) वर्ष की अवधि का होगा।

8.2 शोधार्थी को पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (02) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बशर्ते, पी-एच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (08) वर्ष से अधिक नहीं हो।

8.3 इसके अतिरिक्त, महिला पी-एच.डी. शोधार्थियों तथा दिव्यांगों (40% से अधिक दिव्यांगता) को दो (02) वर्षों की अतिरिक्त छुट दी जा सकती है; तथापि, ऐसे प्रकरण में पी-एच.डी. कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु कुल अवधि पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से दस (10) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.4 महिला पी-एच.डी. शोधार्थियों को पी-एच.डी. कार्यक्रम की पूर्ण अवधि में 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(अनुच्छेद 4: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

8.5 यदि कोई शोधार्थी निर्धारित अवधि (03 वर्ष) के अंत में शोध प्रबंध जमा करने में विफल रहता है तो संबन्धित वि.शो.स. संबन्धित शोध सलाहकार समिति (शो.स.स.) के अनुरोध पर एक समय में एक वर्ष तथा कुल तीन वर्ष (03) तक का विस्तार स्वीकृत कर सकती है। किसी भी स्थिति में शोधार्थी के प्रवेश की तिथि से शोध प्रबंध जमा करने की अवधि की गणना छह (06) वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसे शोधार्थी को विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद में किसी भी प्रकरण पर लिए गए निर्णय से इतर अतिरिक्त अवधि हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान नहीं करेगा।

8.6 छह (06) वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात, शोधार्थी को पुनःपंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए शोधार्थी को उन कारणों को बताते हुए आवेदन करना होगा जिनके कारण वह शोध प्रबंध जमा नहीं कर सका। ऐसे आवेदन को संबन्धित शो.स.स. एवं वि.शो.स. द्वारा विधिवत अग्रेषित तथा अनुशंसित किया जाएगा। पुनः पंजीकरण की स्वीकृति के पश्चात, शोधार्थी दो (02) वर्ष के भीतर किसी भी समय अपना शोध प्रबंध जमा कर सकता है।

8.7 शोध प्रबंध जमा करने की न्यूनतम अवधि (03 वर्ष) का मानदण्ड पुनः पंजीकरण प्रकरणों में लागू नहीं होगा।

9. कोर्स वर्क

9.1 पी-एच.डी. जमा करने हेतु कोर्स वर्क एक पूर्वापेक्षित शर्त है।

9.2 कोर्स वर्क न्यूनतम एक सेमेस्टर की अवधि का होगा। समस्त नामांकित पी-एच.डी. शोधार्थियों को संबन्धित विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कोर्स वर्क पूर्ण करना होगा।

9.3 पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले समस्त शोधार्थियों से प्रारंभिक दो सेमेस्टर्स के दौरान निर्धारित कोर्स वर्क पूर्ण करना होगा।

9.4 यदि कोई पी-एच.डी. शोधार्थी कोर्स वर्क परीक्षा में किन्हीं कारणों से असफल हो जाता है या परीक्षा में भाग नहीं लेता है, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक और अवसर दिया जाएगा। यदि वह दोबारा असफल होता है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

9.5 पी-एच.डी. कार्यक्रम न्यूनतम 12 क्रेडिट्स का होगा, जिसमें यूजीसी द्वारा 2019 में डी.ओ.सं.एफ.1-1/2018 (जर्नल/केयर) अधिसूचित “शोध एवं प्रकाशन नैतिकता” पाठ्यक्रम तथा एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम समाहित होगा। संबन्धित शो.स.स. पी-एच.डी. कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट्स के अंश के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भी अनुशंसा कर सकती है। (अनुच्छेद 9: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)।

9.6 किसी पी-एच.डी. शोधार्थी को कार्यक्रम में बने रहने और अपना शोध प्रबंध जमा करने हेतु पात्र होने के लिए कोर्स वर्क में यूजीसी 10-पॉइंट स्केल में न्यूनतम 55% अंक या इसके समकक्ष श्रेणी प्राप्त करनी होगी। (अनुच्छेद 9: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)।

9.7 विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रम क्रेडिट्स, उत्तीर्णता मानदण्ड एवं अन्य संबन्धित प्रकरणों का विवरण तत्कालीन यूजीसी विनियमों के अनुरूप होगा।

9.8 पी-एच.डी. हेतु निर्धारित समस्त पाठ्यक्रम संबन्धित अध्ययन मंडल/संकाय मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किए जाएंगे। ऐसे पाठ्यक्रम उसी संकाय/विभाग से हो सकते हैं जहां शोधार्थी नामांकित है या शोध क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर अन्य संकायों से भी हो सकते हैं।

9.9 कोर्स वर्क की पूर्णता के पश्चात शोधार्थी को एक व्यापक परीक्षा में भाग लेना होगा, परीक्षा की प्रक्रिया संबन्धित विभाग/संकाय या विश्वविद्यालय स्तर पर तय की जाएगी।

9.10 केवल उन्हीं शोधार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनकी उपस्थिति कोर्स वर्क अवधि के दौरान 75% या उससे अधिक है। संबन्धित विभाग उपस्थिति का सत्यापन करेगा। बाह्य पूर्णकालिक शोधार्थियों के प्रकरण में संबन्धित संस्थानों के प्रमुख तत्संबन्धित विभागाध्यक्ष को उपस्थिति की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे जहां शोधार्थी नामांकित है। तत्संबन्धित विभागाध्यक्ष इसे परीक्षा नियंत्रक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के कार्यालय में प्रेषित करेंगे।

9.11 वि.शो.स. द्वारा शो.स.स. के माध्यम से प्राप्त समस्त नामांकित शोधार्थियों की प्रथम प्रगति रिपोर्ट शोध/पी-एच.डी. अनुभाग को प्रेषित की जाएगी।

10. शोध प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण एवं पंजीकरण

10.1 किसी शोधार्थी द्वारा प्रथम शुल्क जमा करने के साथ ही उसे कार्यक्रम में अस्थायी रूप से पंजीकृत माना जाएगा। पंजीकरण की तिथि प्रथम प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि होगी।

10.2 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने तथा (विनियम 9 के अनुच्छेद (3) में निर्धारित अंक/श्रेणी प्राप्त करने पर) पी-एच.डी. शोधार्थी द्वारा शोध कार्य पूर्ण करना तथा शोध प्रबंध/शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

10.3 शोधार्थी द्वारा कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के एक माह के भीतर, प्रस्तावित शोध कार्य पर शीर्षक सहित शोध कार्य प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में शो.स.स. के माध्यम से वि.शो.स. को प्रस्तुत करेगा।

10.4 वि.शो.स. शोधार्थी की प्रस्तुति सहित उसके शोध कार्य प्रस्ताव की जांच करेगी। समिति "शोध कार्य प्रस्ताव संगोष्ठी" के मूल्यांकन हेतु एक बाह्य विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करेगी, जो इस विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं होना चाहिए।

10.5 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु वि.शो.स. बाह्य विशेषज्ञों के न्यूनतम तीन नामों का एक पैनल प्रेषित करेगी जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से नीचे के न हों। अनुमोदित नाम इसकी अधिसूचना तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेंगे।

10.6 शोध प्रस्ताव से संतुष्ट होने पर वि.शो.स. प्रस्ताव एवं शोध के विषय को अनुमोदित करेगी। यदि वि.शो.स. द्वारा किसी संशोधन/परिवर्तन/सुधार का सुझाव दिया जाता है तो शोधार्थी तदनुसार अपने शोध कार्य प्रस्ताव को संशोधित करेगा तथा पर्यवेक्षक के इस अनुमोदन के साथ कि उक्त परिवर्तन सम्मिलित कर लिए गए हैं, वि.शो.स. के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना होगा।

10.7 यदि वि.शो.स. शोध कार्य प्रस्ताव की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है तो शोधार्थी को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा वि.शो.स. द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर इस हेतु संगोष्ठी आयोजित की जाएगी (यह अवधि किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक नहीं होगी)। संगोष्ठी उपरांत शोध कार्य प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। परंतु यदि केवल संगोष्ठी ही असंतोषजनक है, तो शोधार्थी को एक माह के भीतर संगोष्ठी की पुनः प्रस्तुति करनी होगी।

10.8 यदि कोई शोधार्थी उपर्युक्त निर्दिष्ट समय के भीतर शोध कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। शोध कार्य प्रस्ताव संगोष्ठी के समापन के पश्चात शोधार्थी को शो.स.स. के माध्यम से अनुमोदित विषय पर शोध कार्य प्रस्ताव वि.शो.स. के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

10.9 वि.शो.स. प्रस्तुत शोध कार्य प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसा शोध/पी-एच.डी. अनुभाग को अग्रेषित करेगी। अनुभाग इसे अनुमोदन हेतु विवि.शो.उपा.स. को अग्रेषित करेगा।

10.10 विवि.शो.उपा.स. अनुमोदन की अधिसूचना विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय द्वारा संबन्धित विभाग, पर्यवेक्षक एवं अध्येता को वि.शो.स. कार्यवृत्त/अनुशंसा (शोध कार्य प्रस्ताव अनुमोदन कार्यवृत्त) की प्राप्ति की तिथि के एक माह के भीतर सूचित की जानी चाहिए।

11. उपस्थिति

11.1 किसी पी-एच.डी. शोधार्थी को विभाग/स्कूल/केंद्र के विभागाध्यक्ष/समन्वयक के कार्यालय में उपलब्ध उपस्थिति पंजी में विश्वविद्यालय के सभी कार्य दिवसों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। शोधार्थी के वि.शो.स. तथा/या विवि.शो.उपा.स. द्वारा अनुमोदित ज्युटी/स्वीकृत अवकाश पर होने की स्थिति में उपस्थिति की अनिवार्यता शिथिल रहेगी।

11.2 उपस्थिति तथा अवकाश के नियम बाह्य पूर्णकालिक शोधार्थियों पर भी लागू होंगे तथा उन्हें तत्संबन्धित केंद्र से अपेक्षित उपस्थिति का संबन्धित विभागाध्यक्ष के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करना होगा जहां वह अपने सह-पर्यवेक्षक (कोर्स वर्क से इतर प्रकरण में) के माध्यम से अपना शोध कर रहे हैं।

12. अनिवार्य निवास अवधि

12.1 एक पूर्णकालिक पी-एच.डी. शोधार्थी को किसी एकल अवधि में अनिवार्य रूप से दो वर्ष तक विश्वविद्यालय में उपस्थित रहना होगा, जिसे निवास अवधि के रूप में जाना जाएगा। वह इस अवधि में नियमित सैवतनिक समनुदेशन नहीं ले सकता है। मातृत्व/बाल देखभाल अवकाश के संदर्भ में नियमानुसार अनिवार्य निवास अवधि पूर्ण करनी होगी।

12.2 आंतरिक पूर्णकालिक शोधार्थी हेतु अनुच्छेद 6.4.2. में वर्णित तथा अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थी अनुच्छेद 6.4.4. एवं 6.4.5. में वर्णित कोर्स वर्क पूर्ण करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम अवधि निवास अवधि होगी (अर्थात् छह माह)।

13. अवकाश नियम

13.1 एक पी-एच.डी. शोधार्थी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों के अवकाश का पात्र होगा। वह किसी भी अंतर-सेमेस्टर अवकाश, शीत एवं ग्रीष्म अवकाश का पात्र नहीं होगा। वह एक कैलेंडर वर्ष में चिकित्सकीय कारणों से 10 दिन तक के अतिरिक्त अवकाश का भी पात्र होगा। उपर्युक्त अवकाश प्रावधान संचयी हैं।

13.2 पुरुष/महिला शोधार्थी अपनी संपूर्ण शोध अवधि के दौरान एक बार विश्वविद्यालय/यूजीसी नियमों के अनुसार पितृत्व/मातृत्व/बाल देखभाल अवकाश के पात्र होंगे।

13.3 अनुच्छेद 13.1 में उल्लिखित अवकाश पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर विद्यालय/केंद्र के विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 13.2 में उल्लिखित प्रसूति एवं बाल देखभाल अवकाश को संबन्धित वि.शो.स. की अनुशंसा पर विवि.शो.उपा.स. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

14. कर्तव्य तथा अध्ययन अवकाश

14.1 यदि कोई पी-एच.डी. शोधार्थी दो (02) सप्ताह या उससे कम अवधि हेतु शोध आंकड़ा संग्रह/शोध क्षेत्र भ्रमण का इच्छुक है, तो वह विभाग/स्कूल/केंद्र के विभागाध्यक्ष/समन्वयक को विधिवत सूचित करते हुए संबन्धित शो.स.स. की अनुशंसा पर ऐसा कर सकता है।

14.2 वि.शो.स. किसी पी-एच.डी. शोधार्थी को 60 दिनों के लिए विश्वविद्यालय के बाहर (विदेश सहित) किसी स्थान पर अपने शोध कार्य के एक अंश को आगे बढ़ाने की अनुशंसा कर सकती है। यदि ऐसी अनुशंसाएं 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए हैं, तो वि.शो.स. की अनुशंसाएं वि.वि.शो.उपा.स. के समक्ष रखी जाएंगी, जो इन विनियमों में निर्धारित शोध प्रबंध जमा करने की अधिकतम समय सीमा को पार किए बिना पी-एच.डी. शोधार्थी को विश्वविद्यालय के बाहर (विदेश सहित) किसी स्थान पर अपने शोध कार्य के एक अंश को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकती है।

15. वित्तीय सहायता

15.1 पूर्णकालिक पी-एच.डी. शोधार्थी निधीयन अभिकरणों (उदाहरणार्थ यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही विश्वविद्यालय शोध अध्येतावृत्ति) द्वारा निर्धारित राशि की छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति (आकस्मिक अनुदान सहित) के समय-समय पर पात्र होंगे, जोकि यूजीसी या उसके क्रमानुयायी/अन्य निधीयन अभिकरणों से धन की उपलब्धता के अधीन होगा। छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति से संबन्धित निधियां अभिकरण की शर्त-पूर्ति के अधीन होंगी।

15.2 यूजीसी-विश्वविद्यालय शोध अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि तीन वर्ष की है, जो सेमेस्टर के आधार पर शोधार्थी के संतोषजनक शोध प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षक से सेमेस्टर-वार निरंतरता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

संबन्धित वि.शो.स. की अनुशंसा तथा यूजीसी से धन की उपलब्धता के अधीन पंजीकृत शोधार्थियों को प्राप्त अध्येतावृत्ति एक अतिरिक्त वर्ष हेतु स्वीकृत की जा सकती है। यदि शोधार्थी के पास विभिन्न निधीयन अभिकरणों से अपनी स्वर्जित अध्येतावृत्ति है, तो संबन्धित निधीयन अभिकरण के नियम एवं शर्तें ऐसे शोधार्थियों पर लागू होंगी।

16. शोध प्रबंध का पूर्व-प्रस्तुतीकरण

16.1 शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व शोधार्थी को शोध प्रकोष्ठ/अनुभाग के कार्यालय में न्यूनतम छह अर्ध-वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जमा करने होंगे।

16.2 संबन्धित शो.स.स. एवं वि.शो.स. प्रत्येक शोधार्थी की शैक्षणिक/शोध प्रगति की निगरानी करेंगी। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक शोधार्थी प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र पर प्रगति प्रतिवेदन अपने पर्यवेक्षक एवं सह-पर्यवेक्षक, यदि कोई हों, के माध्यम से संबन्धित शो.स.स. को प्रस्तुत करेगा।

16.3 प्रत्येक छमाही में शोधार्थी को एक संगोष्ठी के माध्यम से संबन्धित शो.स.स. के समक्ष शोध कार्य की प्रगति प्रस्तुत करनी होगी, जो शोधार्थी द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करेगी तथा संबन्धित क्षे.प. के समक्ष अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

16.4 वि.शो.स. के अध्यक्ष विशिष्ट अनुशंसाओं के साथ प्रगति प्रतिवेदन संबन्धित अधिष्ठाता के माध्यम से शोध प्रकोष्ठ/अनुभाग को अग्रेषित करेंगे।

16.5 किसी भी सेमेस्टर/छमाही में किसी शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक मानी जाएगी यदि वह इन नियमों में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है।

16.6 पी-एच.डी. शोधार्थी शोध प्रबंध जमा करने तक प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। शोधार्थी को अंतिम प्रगति रिपोर्ट शोध प्रबंध जमा करने से तीन दिन पूर्व निर्धारित रूप में शोध प्रकोष्ठ/अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

16.7 शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व, पी-एच.डी. शोधार्थी को संबन्धित वि.शो.स. के समक्ष एक प्रस्तुति देनी होगी, जिसमें समस्त संकाय सदस्य, शोधार्थी/विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)। संबन्धित पर्यवेक्षक शिक्षकों एवं अन्य शोधकर्ताओं को अवगत कराने के लिए विद्यालय/केंद्र के विभागाध्यक्ष/समन्वयक के परामर्श से पूर्व-प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी (शोध प्रबंध जमा करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित अवधि अर्थात् 03 वर्ष से पहले नहीं) आयोजित करेंगे जहां शोधार्थी अपने कार्य पर सुधार हेतु सुझाव प्राप्त करेंगे। संबन्धित शो.स.स. एवं वि.शो.स. इस संगोष्ठी के माध्यम से शोधार्थी के कार्य का आकलन करेंगी। संगोष्ठी विभाग में आयोजित की जाएगी तथा इसमें समस्त संकाय सदस्य, शोधार्थी/विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। प्राप्त सुझावों को अनिवार्यतः शोध प्रबंध प्रारूप में शोधार्थी से सम्मिलित कराना पर्यवेक्षक का उत्तदायित्व होगा।

16.8 यदि संबन्धित शो.स.स. तथा/या वि.शो.स. शोधार्थी के कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे अपना कार्य आगे बढ़ाते हुए वि.शो.स. द्वारा निर्दिष्ट एक अवधि के पश्चात पुनः एक संगोष्ठी देनी होगी।

16.9 यदि वि.शो.स. शोधार्थी की पूर्व-प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी से संतुष्ट है, तो समिति के अध्यक्ष पूर्व-प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी के संतोषजनक समापन का प्रमाणपत्र, शोध प्रबंध के सटीक शीर्षक के साथ शोध प्रबंध जमा करने हेतु शोधार्थी के आवेदन की एक प्रति परीक्षा नियंत्रक तथा एक प्रति संबन्धित अधिष्ठाता को अग्रेषित करेंगे। जो तिथि शोध प्रबंध प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की गई है, उसके पश्चात छोड़ी गई किसी भी विस्तारित निवास अवधि को उक्त तिथि पर समाप्त माना जाएगा।

16.10 शोध प्रबंध का सटीक शीर्षक (यदि कोई संशोधन हो) पूर्व-प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी के पश्चात वि.शो.स. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

17. शोध विषय में परिवर्तन

17.1 शोध कार्य प्रस्ताव जमा करने के पश्चात शोध शीर्षक में कोई बड़ा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि शोधार्थी एवं उसके पर्यवेक्षक की राय है कि मामूली बदलाव आवश्यक हैं, तो वह संबन्धित वि.शो.स. के माध्यम से आंशिक परिवर्तन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, जो इसको अनुमोदन के पश्चात परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को सूचित करेगी। पूर्व-प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी से पूर्व या बाद में ऐसे परिवर्तनों की अनुमति शोधार्थी को केवल एक बार ही दी जाएगी।

18. शोध प्रबंध की भाषा

18.1 भाषा विशेष से संबन्धित शोध प्रबंधों को छोड़कर, शोध प्रबंध की भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी होगी।

18.2 शोध प्रबंध की भाषा अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा होने की स्थिति में शोधार्थी को एक पृष्ठ का शोध सारांश अंग्रेजी में जमा करना अनिवार्य होगा।

19. अनुचित साधन एवं साहित्यिक चोरी

19.1 यदि किसी पी-एच.डी. शोधार्थी को अनुचित साधन अपनाने या किसी अन्य के कार्य को चुराने तथा उसे उचित स्वीकृति, श्रेय एवं संदर्भ के बिना अपने शोध कार्य में सम्मिलित करने का दोषी पाया जाता है तो विश्वविद्यालय नियमानुसार शोधार्थी पर ऐसी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है जो शोध कार्य की नैतिकता एवं आचार संहिता के तथा विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता के अनुकूल हो।

19.2 सभी शोध प्रबंधों को यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक नैतिकता को बढ़ावा देने एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियम, 2018 के अनुपालन में होना चाहिए।

19.3 विश्वविद्यालय ऐसे समस्त अनैतिक कार्यों/प्रकरणों का स्वतः संज्ञान ले सकता है अथवा ऐसे प्रकरणों को कोई भी व्यक्ति विभागाध्यक्ष/स्कूल के समन्वयक/ संबन्धित अधिष्ठाता के माध्यम से विश्वविद्यालय को सूचित कर सकता है।

19.4 पशुओं तथा अन्य जीवों, ट्रांसजेनेटिक बीजों एवं खतरनाक सामग्रियों से जुड़े कार्यों के लिए यूजीसी एवं अन्य संबन्धित एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पशु नैतिकता दिशा-निर्देशों एवं जैव-सुरक्षा अनुशंसाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

19.5 विश्वविद्यालय को शोध कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला एक तंत्र विकसित करना होगा जो पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए अग्रणी समस्त शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा तथा उन शोध संबंधी आचरणों को बढ़ावा देगा जिनका उल्लेख यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक नैतिकता का प्रोत्साहन एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम विनियम, 2018 में किया गया है। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

19.6 प्रत्येक पी-एच.डी. शोधार्थी को मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध जमा करना होगा। इसके साथ ही-(क) उसे एक वचनपत्र देना होगा कि उसके शोध कार्य में कोई साहित्यिक चोरी नहीं है तथा (ख) उसे अपने शोध प्रबंध की मौलिकता को प्रमाणित करने के लिए शोध पर्यवेक्षक से एक प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा कि शोध प्रबंध किसी अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

20. शोध प्रबंध जमा करने की प्रक्रिया

20.1 प्रत्येक शोधार्थी को अपने पूर्व-प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी की तिथि से छह माह के भीतर शोध प्रबंध जमा करना अनिवार्य है (इन नियमों में अन्यत्र निर्धारित शोध प्रबंध जमा करने हेतु अधिकतम समय सीमा को पार किए बिना), ऐसा न करने पर उसे पुनः पूर्व-प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी देनी होगी।

20.2 शोध प्रबंध जमा करने से एक माह पूर्व शोधार्थी को परीक्षा नियंत्रक/पी-एच.डी. अनुभाग के कार्यालय में शोध प्रबंध के सारांश की छह (06) प्रतियां जमा करनी होंगी, जो संबन्धित विभागाध्यक्ष/स्कूल या केंद्र के समन्वयक द्वारा विधिवत अग्रेषित की गई हों जिसमें उसके कार्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन हो।

20.3 प्रत्येक शोधार्थी को शोध प्रबंध की हार्ड कॉपी के साथ गैर-संपादित/सुरक्षित पीडीएफ प्रारूप में शोध प्रबंध की एक (01) सॉफ्ट कॉपी सीडी/पेन ड्राइव में जमा करनी होगी।

20.4 शोधार्थी को शोध प्रबंध की छह (06) हार्डबाउंड मुद्रित प्रतियां परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करनी होंगी, जो विभागाध्यक्ष/स्कूल या केंद्र के समन्वयक द्वारा विधिवत अग्रेषित की गई हों। शोध प्रबंध में निर्धारित प्रपत्र में पर्यवेक्षक का प्रमाणपत्र, शोधार्थी घोषणापत्र, कोर्स वर्क पूर्ण करने का प्रमाणपत्र, पूर्व-प्रस्तुतीकरण पूर्ण करने का प्रमाणपत्र, स्वामित्वाधिकार हस्तांतरण प्रमाणपत्र, साहित्यिक चोरी विरोधी प्रमाणपत्र तथा समय-समय पर अपेक्षित अन्य प्रमाणपत्र सम्मिलित होंगे।

20.5 शोध प्रबंध के आवरण एवं शीर्षक पृष्ठ का प्रतिरूप परिशिष्ट XIV एवं अनुलग्नक II के रूप में संलग्न किया गया है। शोधार्थी को इनका दृढ़ता से अनुपालन करना होगा।

20.6 शोध प्रबंध मूल शोध कार्य का एक भाग होना चाहिए जिसकी विशेषता तथ्यों की खोज या अत्यधिक महत्व के किसी व्यावहारिक कार्य पर तथ्यों या सिद्धांतों की व्याख्या के लिए नये दृष्टिकोण से की गई हो। किसी भी शोध प्रकरण में यह शोधार्थी की आलोचनात्मक जांच एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित करनी चाहिए और साहित्यिक प्रस्तुति की दृष्टि से भी संतोषजनक होनी चाहिए।

20.7 एक बार जमा किए गए शोध प्रबंध को दोबारा जमा नहीं किया जा सकता है जब तक कि परीक्षक शोध प्रबंध के पुनरीक्षण हेतु अनुशंसा न करें।

21. मूल्यांकन एवं आकलन प्रक्रिया:

21.1 संबन्धित वि.शो.स. के माध्यम से पर्यवेक्षक छह (06) बाह्य विद्वानों का एक पैनल निर्धारित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। प्रस्तावित पैनल में देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और किसी भी स्थिति में एक ही राज्य से दो (02) और एक ही विश्वविद्यालय से एक (01) से अधिक विद्वानों के नाम नहीं होने चाहिए। जहां भी संभव हो, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। बाह्य परीक्षक को क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशनों का अच्छा रिकॉर्ड रखने वाला शिक्षाविद् होना चाहिए। कुलपति छह (06) से अधिक विशेषज्ञों के नाम भी माँग सकते हैं। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

21.2 बाह्य विशेषज्ञ पैनल में सामान्यतया प्रोफेसर (या समकक्ष) के नाम सम्मिलित होंगे। इस पैनल में अधिकतम एक नाम एसोसिएट प्रोफेसर (या समकक्ष) का हो सकता है। इससे नीचे के पद की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21.3 शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुझाए गए परीक्षकों का पी-एच.डी. शोधार्थियों के साथ-साथ शोध पर्यवेक्षक के साथ रक्त संबन्ध नहीं हो।

21.4 परीक्षक पैनल में शोधार्थी के पर्यवेक्षक एवं सह-पर्यवेक्षक के संस्थान से कोई नाम नहीं होना चाहिए।

21.5 ऐसे शोधार्थी के प्रकरण में जिसने अपने काम का कोई अंश किसी अन्य संस्थान में किया है, बाह्य परीक्षकों के पैनल में उस संस्थान में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा।

21.6 यदि शोध क्षेत्र का विषय ऐसा है कि देश में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में पैनल में विदेश के विशेषज्ञों के नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं।

21.7 शोधार्थी के पर्यवेक्षक आंतरिक परीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

21.8 तदन्तर, कुलपति बाह्य परीक्षक के रूप में पैनल से दो (02) नामों का चयन करके उनकी नियुक्ति करेंगे। यह नाम परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सूचित किए जाएंगे।

21.9 परीक्षा नियंत्रक परीक्षकत्व की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए शोध सारांशिका की एक प्रति भेज कर प्रत्येक परीक्षक से संपर्क करेंगे। इस प्रयोजन हेतु, यदि परीक्षक का ई-मेल उपलब्ध है, तो शीघ्रातिशीघ्र सहमति प्राप्त करने के लिए उनसे ई-मेल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। तथापि, यदि परीक्षा नियंत्रक को प्रथम संप्रेषण से दो सप्ताह की अवधि के भीतर बाह्य परीक्षक से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तब बाह्य परीक्षक को एक अनुस्मारक भेजा जाएगा, यदि अनुस्मारक की तिथि से दो सप्ताह के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो बाह्य परीक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा कुलपति वर्तमान परीक्षकों के पैनल से एक नये परीक्षक की नियुक्त करेंगे।

21.10 प्रत्येक पी-एच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक (आंतरिक परीक्षक) एवं न्यूनतम दो बाह्य परीक्षकों (कुलपति द्वारा चयनित) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पीएचडी विनियम 2022)

21.11 सभी परीक्षकों को अपनी रिपोर्ट निर्दिष्ट प्रपत्र में भेजनी होगी।

21.12 किसी भी शोध प्रबंध को तभी स्वीकार किया जायेगा जब सभी परीक्षक शोध प्रबंध को स्वीकार करने की/उनके द्वारा सुझाए गए किसी भी सुधार को सम्मिलित करने के पश्चात शोध प्रबंध को स्वीकार करने की अनुशंसा करते हैं। यदि बाह्य परीक्षकों में से कोई एक अस्वीकृति की अनुशंसा करता है तो विश्वविद्यालय शोध प्रबंध को परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे बाह्य परीक्षक को भेजेगा। यदि वैकल्पिक परीक्षक शोध प्रबंध को स्वीकार करने की अनुशंसा नहीं करता है तो शोध प्रबंध अस्वीकार हो जाएगा तथा पी-एच.डी. शोधार्थी को पी-एच.डी. प्रदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब सभी परीक्षक शोध प्रबंध को स्वीकार करने की अनुशंसा करते हैं। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)।

21.13 यदि एक परीक्षक स्वीकार करता है तथा दूसरा प्रमुख पुनरीक्षण का सुझाव देता है, तो संबन्धित वि.शो.स. शोधार्थी एवं उसके पर्यवेक्षक को वि.शो.स. की संतुष्टि के लिए आवश्यक परिवर्तन सम्मिलित करने हेतु सूचित करेगी। यदि बाह्य परीक्षक ने संशोधन के पश्चात शोध प्रबंध को पुनः भेजने का अनुरोध किया है तो उसे परीक्षक को भेजा जाएगा।

21.14 विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध जमा करने की तिथि से छह (6) माह की अवधि के भीतर मौखिक परीक्षा परिणाम की घोषणा सहित पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)।

21.15 अन्य बातों के अतिरिक्त, मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के आधार पर मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक शामिल होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा में शोध सलाहकार समिति के सदस्य/संबन्धित विभागाध्यक्ष/विद्यालय/केंद्रों के समन्वयक/संकाय सदस्य/शोधार्थी, विद्यार्थी तथा अन्य इच्छुक विशेषज्ञ/शोधकर्ता सम्मिलित हो सकते हैं। (अनुच्छेद 11: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)

22. उपाधि प्रदान करने की प्रक्रिया

22.1 सामान्य तौर पर पी-एच.डी. की उपाधि उस विषय/विभाग में प्रदान की जाएगी जहां शोधार्थी पंजीकृत है।

22.2 उपाधि प्रदान करने की तिथि विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध जमा करने की तिथि होगी। तथापि, पुनरीक्षण के प्रकरण में जमा करने की तिथि पुनरीक्षित शोध प्रबंध जमा करने की तिथि होगी।

22.3 शोध प्रबंध जमा करने तथा उसे स्वीकृत होने के पश्चात, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय शोधार्थी को इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

22.4 विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर मौखिक परीक्षा परिणाम की घोषणा सहित पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

23. अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया

23.1 वास्तविक उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर समन्वित दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी।

23.2 पी-एच.डी. उपाधि की वास्तविक प्रदानता से पूर्व, विश्वविद्यालय शोधार्थी को इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पी-एच.डी. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पी-एच.डी. विनियम 2016/2022 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जा रही है। (अनुच्छेद 15: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)।

24. पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया

निम्नलिखित में से किसी भी एक परिस्थिति में पी-एच.डी. शोधार्थी का पंजीकरण वि.शो.स. द्वारा निरस्त किया जा सकता है :

24.1 यदि कोई शोधार्थी पर्यवेक्षक के माध्यम से नियमित रूप से दो वर्षों की (अर्थात् चार अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन) संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

24.2 यदि कोई शोधार्थी पूर्व सूचना/अवकाश की मंजूरी के बिना निरंतर चार सप्ताह की अवधि तक अनुपस्थित रहता है।

24.3 यदि कोई शोधार्थी निर्धारित समय के भीतर शोध सारांश प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

24.4 यदि कोई शोधार्थी इन विनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन किसी भी सेमेस्टर में अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करने में विफल रहता है।

24.5 यदि कोई शोधार्थी इन विनियमों में दिए गए अधिकतम निर्धारित समय के भीतर शोध प्रबंध जमा करने में विफल रहता है।

24.6 यदि कोई शोधार्थी पी-एच.डी. कार्यक्रम छोड़ देता है तथा उसके शोध पर्यवेक्षक की ओर से शोधार्थी द्वारा शोध कार्य छोड़ने की विधिवत अनुशंसा की जाती है।

24.7 यदि कोई शोधार्थी कदाचार तथा/या अनुशासनहीनता के कृत्य में सम्मिलित पाया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी ने उसकी बर्खास्तगी की अनुशंसा की है।

24.8 यदि कोई शोधार्थी निर्धारित समय के भीतर शुल्क जमा करने में विफल रहता है।

25. अस्थायी निर्गमन (विपंजीकरण एवं पुनःपंजीकरण)

25.1 पीएच.डी. शोधार्थी को वि.शो.स. की अनुशंसा पर विवि.शो.उपा.स. द्वारा कुछ विशिष्ट कारणों के चलते अस्थायी रूप से कार्यक्रम से हटने की अनुमति दी जा सकती है (जिसे 'विपंजीकरण' कहा जाता है) एवं बाद में शोध को पूर्ण करने के लिए वापस सम्मिलित होने (जिसे 'पुनःपंजीकरण' कहा जाता है) तथा इन विनियमों में अन्यत्र उल्लिखित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम निर्धारित समय सीमा को पार किए बिना शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह निर्गमन संपूर्ण या आंशिक सेमेस्टर्स के लिए हो सकता है तथा पी-एच.डी. शोध के पूर्ण कार्यकाल में केवल एक बार प्रदान किया जाएगा। निम्नलिखित कारणों में से किसी एक की स्थिति में अस्थायी निर्गमन की अनुमति दी जा सकती है:

25.1 (i) यदि शोधार्थी को कोई व्यवसाय/रोजगार मिला है तथा उसने निवास अवधि पूर्ण कर ली है।

25.1 (ii) यदि कोई पूर्णकालिक प्रायोजित शोधार्थी शोध प्रबंध जमा करने हेतु न्यूनतम निवास अवधि की शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात अपने मूल संगठन में वापस सम्मिलित हो जाता है।

25.2 मातृत्व अवकाश के प्रकरण को छोड़कर, उपर्युक्त छूट का लाभ न्यूनतम निवास अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही लिया जा सकेगा।

25.3 पुनःपंजीकरण की स्थिति में शोधार्थी को विपंजीकरण अवधि के शुल्कों का भुगतान करना होगा तथा इस अवधि का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय पर जमा करना होगा।

26. इन्फ्लिबनेट डिपॉज़िटरी

मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तथा पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय पी-एच.डी. शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इन्फ्लिबनेट पर होस्ट करने के लिए जमा करेगा ताकि इसे सभी संस्थानों के लिए सुलभ बनाया जा सके। (अनुच्छेद 7: यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022)।

27. शोध समितियां

अकादमिक परिषद के अधीन, निम्नलिखित समितियां इन विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. कार्यक्रम से संबन्धित समस्त प्रकरणों पर निर्णय लेंगी:

- 1) विश्वविद्यालय की शोध उपाधि समिति (विवि.शो.उपा.स.)
- 2) विभागीय/विद्यालय/केंद्र शोध समिति (वि.शो.स.)

3) शोध सलाहकार समिति (शो.स.स.)

27.1 विवि.शो.उप.स. में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे (विश्वविद्यालय के अध्यादेश 46 की धारा 2 के अनुसार):

i)	कुलपति/सम-कुलपति (पदेन)	अध्यक्ष
ii)	अधिष्ठाता (पदेन)	सदस्य
iii)	विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय परिसरों/केंद्रों/विभागों के प्रमुख (आवर्तन द्वारा) जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी	सदस्य
iv)	प्रोफेसर जो अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष नहीं हैं (आवर्तन द्वारा) जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी	सदस्य
v)	कुलपति द्वारा नामित किए गए विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय परिसरों/केंद्रों में विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व कर रहे चार एसोसिएट प्रोफेसर	सदस्य
vi)	कुलपति द्वारा नामित किए गए विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व कर रहे चार बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य
vii)	कुलसचिव	सचिव (पदेन)

कुलसचिव एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम दो बार विवि.शो.उप.स. की बैठकें आहूत करेंगे।

विवि.शो.उप.स. के कार्य विश्वविद्यालय के अध्यादेश 46 की धारा 2 के अनुसार होंगे। विवि.शो.उप.स. का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।

पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

27.2 वि.शो.स. में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

i)	विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
ii)	विभाग के समस्त प्रोफेसर	सदस्य
iii)	आवर्तन द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों पर वरिष्ठता के अनुसार विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर	सदस्य
iv)	आवर्तन द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों पर वरिष्ठता के अनुसार विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर	सदस्य
v)	संबन्धित पी-एच.डी. अध्येता के पर्यवेक्षक एवं सह-पर्यवेक्षक (यदि कोई हों)	सदस्य
vi)	एक बाह्य विशेषज्ञ जो प्रोफेसर के पद से नीचे का नहीं हो*	सदस्य

विभाग/स्कूल/केंद्र में तीन या तीन से कम पात्र शिक्षक होने की स्थिति में, वि.शो.स. में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

i)	संबन्धित संकाय के अधिष्ठाता	अध्यक्ष
ii)	विभाग के समस्त पात्र शिक्षक	सदस्य
iii)	विभागाध्यक्ष के परामर्श से अधिष्ठाता द्वारा नामित सह-विभाग के एक वरिष्ठ शिक्षक	सदस्य
iv)	एक बाह्य विशेषज्ञ जो प्रोफेसर के पद से नीचे के नहीं हों*	सदस्य

* केवल सारांश प्रस्तुतीकरण/शोध योजना प्रस्ताव संगोष्ठी के समय, ऐसे नामांकन एक (01) वर्ष हेतु वैध।

वि.शो.स. सचिव या समन्वयक के रूप में आवर्तन द्वारा अपने किसी सदस्य की नियुक्ति करेगी।

27.3 शो.स.स. में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

प्रत्येक पी-एच.डी. शोधार्थी हेतु एक शोध सलाहकार समिति (शो.स.स.) होगी। संबन्धित पी-एच.डी. शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का समन्वयक होगा तथा इस समिति के निम्नलिखित दायित्व होंगे:

27.3.4 शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना एवं शोध के विषय को अंतिम रूप देना।

27.3.5 अध्ययन अभिकल्पना एवं शोध की पद्धति विकसित करने में पी-एच.डी. शोधार्थी का मार्गदर्शन करना तथा उस पाठ्यक्रम की पहचान करना जिसका उसे अध्ययन करना आवश्यक है।

27.3.6 पी-एच.डी. शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना एवं उसकी सहायता करना।

(2) प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक पी-एच.डी. शोधार्थी एक प्रस्तुति देने के लिए शो.स.स. के समक्ष उपस्थित होगा तथा मूल्यांकन एवं आगामी मार्गदर्शन हेतु अपने कार्य की प्रगति पर एक लघु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। शो.स.स. विश्वविद्यालय को पी-एच.डी. शोधार्थी की प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। ऐसी अनुशंसाओं की एक प्रति पी-एच.डी. शोधार्थी को भी प्रदान की जाएगी।

(3) यदि पी-एच.डी. शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक है तो शो.स.स. इसके कारणों को दर्ज करेगा तथा सुधारात्मक उपाय सुझाएगा। यदि पी-एच.डी. शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहता है तो शो.स.स. विशिष्ट कारणों के साथ पी-एच.डी. कार्यक्रम से पी-एच.डी. शोधार्थी के पंजीकरण को निरस्त करने की अनुशंसा कर सकता है। (अनुच्छेद 10: यूजीसी पीएचडी विनियम 2022)।

i)	संबन्धित पी-एच.डी. शोधार्थी के आंतरिक पर्यवेक्षक	समन्वयक
ii)	संबन्धित पी-एच.डी. शोधार्थी के सह-पर्यवेक्षक/बाह्य पर्यवेक्षक (यदि कोई हों)	सदस्य
iii)	वि.शो.स. अध्यक्ष द्वारा नामित	सदस्य
iv)	पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर सह/समवर्गी विषय/विभाग से एक सदस्य	सदस्य

कोई शिक्षक जो पी-एच.डी. शोधार्थी का मार्गदर्शन करने का पात्र नहीं है, वह उपरलिखित किसी भी शोध समिति का सदस्य नहीं बन सकता है।

वि.शो.स. ऐसी कोई अनुशंसा नहीं करेगा जो इन विनियमों के अनुरूप न हो।

28. कठिनाई निराकरण: इन विनियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, कोई भी प्रश्न, जो इन विनियमों में सम्मिलित नहीं है, या इन विनियमों से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई पर, अकादमिक परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

29. निरसन: इन पी-एच.डी. विनियमों के प्रभावी होने की तिथि से तत्संबन्धित सभी पिछले नियम/विनियम अप्रभावी हो जाएंगे। यह निरसन इस प्रकार निरस्त किए गए पिछले नियमों को प्रभावित नहीं करेगा या इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी पिछले नियमों के अंतर्गत किए गए या किए गए किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा या इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी नियम के अंतर्गत अर्जित, प्राप्त या उपगत किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

30. शुल्क संरचना: विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित।

प्रो. एन.एस.एच.एन. मूर्ति, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./718/2023-24]

परिशिष्ट-I

अंशकालिक पी-एच.डी. शोध हेतु प्रावधान

1. अंशकालिक पी-एच.डी. शोध हेतु पात्रता

क. किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान का स्थायी/नियमित शिक्षक, बशर्ते कि वह ऐसी उपाधि की आवश्यकता को स्थापित कर सके तथा मूल संस्थान द्वारा विधिवत समर्थित हो, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि ऐसे शिक्षक को कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

ख. एक स्थायी सरकारी कर्मचारी, जो समूह 'बी' सेवाओं (डी.ओ.पी.टी. द्वारा यथा परिभाषित) के पद से नीचे का न हो, बशर्ते कि वह ऐसी उपाधि की आवश्यकता को स्थापित करता हो तथा उसका आवेदन मूल संस्थान द्वारा विधिवत समर्थित हो, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि कर्मचारी को कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

ग. उद्योगों/कॉर्पोरेट क्षेत्र से शोधार्थी:

i. उद्योग/कॉर्पोरेट क्षेत्र को संबन्धित नियामक निकाय जैसे एफएसएसएआई, आईसीएआर, जीएमपी आदि से विधिवत अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

ii. शोधार्थी ने उसी संगठन में न्यूनतम पांच वर्ष की स्थायी/नियमित सेवा पूर्ण की हो, तथा यह समूह 'बी' सरकारी सेवाओं के पद से नीचे का न हो।

iii. संगठनात्मक/सामाजिक उन्नति क्षेत्र में ऐसी उपाधि की आवश्यकता का औचित्य।

iv. पी-एच.डी. पूर्ण होने तक शोधार्थी को उसी संगठन में कार्य करना होगा, यदि वह कार्यक्रम के दौरान संगठन छोड़ देता है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

v. कार्य से उत्पन्न किसी भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का एकमात्र स्वामित्व होगा।

पत्रकारिता एवं जनसंचार हेतु मानदण्ड

i. एबीसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में उप-संपादक/स्टाफ रिपोर्टर/संवाददाता या वरिष्ठ संपादकीय पद पर तीन वर्ष का कार्यानुभव या एबीसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों के डिजिटल संस्करणों/समाचार पोर्टलों से उपर्युक्त या समकक्ष पत्रकारिता का अनुभव। समाचार पत्र/डिजिटल संस्करण/समाचार पोर्टल न्यूनतम छत्तीस (36) माह की अवधि हेतु निर्बाध एवं नियमित रूप से प्रकाशित होना चाहिए। गृह पत्रिकाओं, स्मारिकाओं, वार्षिक पत्रिकाओं, द्विमासिकों, त्रैमासिकों, सोशल मीडिया साइटों, गैर-मान्यता प्राप्त पोर्टलों तथा किसी भी पत्रिका के द्वितीय संस्करण के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. एबीसी उपग्रह समाचार चैनलों में संपादकीय दल/स्टाफ रिपोर्टर या वरिष्ठ संपादकीय पद के रूप में तीन वर्ष का कार्यानुभव। समाचार चैनल कम से कम छत्तीस (36) माह की अवधि हेतु निर्बाध एवं नियमित रूप से परिचालित तथा प्रसारित होना चाहिए। गृह पत्रिकाओं, स्मारिकाओं, वार्षिक पत्रिकाओं, द्विमासिकों, त्रैमासिकों तथा किसी भी पत्रिका के द्वितीय संस्करण के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. सामग्री संपादक/प्रस्तोता/उद्घोषक या एंकर के रूप में तीन वर्ष का कार्यानुभव, या मान्यता प्राप्त रेडियो स्टेशन के रचनात्मक अनुभाग में वरिष्ठ पद। रेडियो स्टेशन कार्याधीन रहना चाहिए तथा श्रोताओं के लिए न्यूनतम छत्तीस (36) माह की अवधि हेतु उपलब्ध होना चाहिए।

iv. केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मीडिया संगठन/सरकारी संगठन/पीएसयू/स्वायत्त निकायों में तीन वर्ष का कार्यानुभव जिनका स्तर वर्ग 'बी' कर्मचारी से कम न हो।

v. आईएनएस या समान निकाय/केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त विज्ञापन/पीआर एजेंसी के रचनात्मक अनुभाग में तीन वर्ष का कार्यानुभव। एजेंसी न्यूनतम छत्तीस (36) माह की अवधि के लिए परिचालन में होनी चाहिए।

vi. रचनात्मक सदस्य के रूप में निर्मित/निर्देशित/योगदान की गई न्यूनतम एक फिल्म/डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रमाणन एवं रिलीज/सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाण के साथ एक मान्यता प्राप्त फिल्म/डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता।

vii. संगठनात्मक/सामाजिक उन्नति में ऐसी उपाधि की आवश्यकता का औचित्य।

viii. पी-एच.डी. पूर्ण होने तक शोधार्थी को उसी संगठन में काम करना होगा, यदि वह कार्यक्रम के दौरान संगठन छोड़ देता है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

ix. कार्य से उत्पन्न किसी भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का एकमात्र स्वामित्व होगा।

2. अंशकालिक शोधार्थियों का प्रवेश तत्कालीन प्रभावी यूजीसी तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नियमों जैसे, यूजीसी पी-एच.डी. विनियम 2022 एवं इंगाराजजावि पी-एच.डी. विनियम 2022 द्वारा शासित होगा। अर्थात् -

क. ऐसे शोधार्थियों का प्रवेश केवल शोध प्रवेश परीक्षा (आरईटी) या नियमों में निर्दिष्ट छूट वाली श्रेणी के माध्यम से होगा। इनके लिए कोई सीधा प्रवेश या कोई विशिष्ट कोटा नहीं होगा।

ख. ऐसे शोधार्थियों को अपेक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए छह माह का अवकाश लेना अनिवार्य है।

ग. वह विश्वविद्यालय से किसी भी अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे।

3. उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा, शोधार्थी को अपने मूल संगठन के उपयुक्त प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" लेकर जमा करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया हो कि:

क. शोधार्थी को अंशकालिक आधार पर शोध करने की अनुमति है।

ख. उसके आधिकारिक कर्तव्य उसे शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

ग. अपेक्षानुसार, उसके द्वारा मांगे जाने पर उसे अवकाश की अनुमति दी जाएगी तथा कर्तव्यों से मुक्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-II

विभागों तथा उनके संबद्ध या सहयोगी विषयों की सूची (यह सूची व्यापक नहीं है एवं पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय पी-एच.डी. कार्यक्रम में नामांकन हेतु है, नौकरी के उद्देश्य से नहीं)।

क्र.सं.	विभाग का नाम	संबद्ध/सहयोगी विषय
1.	वनस्पति विज्ञान	पादप विज्ञान, जैविक विज्ञान (पादप विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ, जीवन विज्ञान (पादप विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ), पर्यावरण विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी (पादप विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ), आनुवंशिकी, जैव सूचना विज्ञान, जैव रसायन, कृषि खाद्य विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान।
2.	जैव प्रौद्योगिकी	वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु विज्ञान, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में एम.टेक., चिकित्सा विज्ञान, जैव अभियांत्रिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान, आनुवंशिकी जैव रसायन।
3.	रसायन विज्ञान	जैव रसायन, सामग्री विज्ञान, औद्योगिक रसायन।
4.	पर्यावरण विज्ञान	वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पशु विज्ञान, जीवन विज्ञान, भूविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, रसायन विज्ञान।
5.	भूगर्भ शास्त्र	पर्यावरण विज्ञान, सिविल अभियांत्रिकी में एम.टेक., खनन एवं धातुकर्म।
6.	गणित	ब्रह्माण्ड विज्ञान।
7.	भौतिकी विज्ञान	ब्रह्माण्ड विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, संघनित पदार्थ भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणु भौतिकी।
8.	सांख्यिकी विज्ञान	गणित, कंप्यूटर विज्ञान, जनसंख्या अध्ययन, कृषि सांख्यिकी, स्वास्थ्य सांख्यिकी सामग्री विज्ञान, जनसांख्यिकी एवं जैव सांख्यिकी।
9.	प्राणी विज्ञान	पशु विज्ञान, जीवन विज्ञान (पशु विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ), जैव रसायन तंत्रिका विज्ञान, आनुवंशिकी, खाद्य विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी (पशु विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ), मत्स्य पालन, कीट विज्ञान।

INDIRA GANDHI NATIONAL TRIBAL UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Amarkantak, the 29th January, 2024

Ph.D. Regulations, 2022

[In accordance with the UGC (Minimum Standards & Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations 2022]

No. IGNTU/RO/2024/88.—

1. Short title, Application and Commencements.

- 1.1. The degree of 'Doctor of Philosophy' shall be abbreviated as 'Ph.D.'
- 1.2. These regulations shall be called the "Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak (henceforth IGNTU, Amarkantak, the University) (Minimum Standard & Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations 2022.
- 1.3. These shall be applicable to all the disciplines/subjects offered by the IGNTU, Amarkantak and its Regional Campuses (henceforth RCs).
- 1.4. These shall come into force from the date of notification issued by the IGNTU, Amarkantak. All previous Ph.D. Regulations issued by the University will become null and void with the date of issuance of these regulations, unless otherwise notified.
- 1.5. Award of degrees to candidates registered for the Ph.D. programme on or after July 11, 2009, till the date of Notification of these Regulations (i.e. UGC/IGNTU Ph.D. regulation 2022) shall be governed by the provisions of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulations, 2016 and IGNTU, Amarkantak Ph.D. Regulations, 2016 as the case may be. Further, the award of degrees to candidates already registered and pursuing Ph.D. shall be governed by these Regulations (i.e. UGC/IGNTU Ph.D. regulation 2022) or UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016 and IGNTU, Amarkantak Ph.D. Regulations, 2016. **(Clause 16: UGC Ph.D. Regulations 2022)**

1.6. Repealed

2. Definitions.

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

- a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- b) "Adjunct Faculty" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach by a Higher Educational Institution;
- c) "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means a measure of the overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses in all semesters and the sum of the total credits of all courses in all semesters. It is expressed up to two decimal places;
- d) "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit;
- e) "College" means an institution engaged in higher education and/or research, either established by a University as its constituent unit or is affiliated with it;
- f) "Commission" means the University Grants Commission established under Section 4 of the UGC Act 1956;
- g) "Course" means one of the specified units which go to comprise a programme of study;
- h) "Course Work" means courses of study prescribed by the School/Department/ Centre to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree;
- i) "Degree" means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22 (3) of the Act;
- j) "External examiner" means an academician/researcher with published research work who is not part of the Higher Educational Institution where the Ph.D. scholar has registered for the Ph.D. programme;

- k) “Foreign Educational Institution” means—(i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode;
- l) “Grade Point” means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale;
- m) “Guide/Research Supervisor” means an academician/researcher recognized by Higher Educational Institution to supervise the Ph.D. scholar for his/her research;
- n) “Higher Educational Institution” means a university or institution specified under clause 2 of Regulation 1 of these Regulations;
- o) “Interdisciplinary Research” means research conducted by a Ph.D. scholar in two or more academic disciplines;
- p) “Open and Distance Learning Mode” shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;
- q) “Online Mode” shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;
- r) “Plagiarism” means the practice of taking someone else’s work or idea and passing them as one’s own;
- s) “Programme” means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the Act;
- t) “Prospectus” means any document, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information relating to a Higher Educational Institution and programmes, to the general public (including to those seeking admission in such Higher Educational Institutions) by the Higher Educational Institutions;
- u) “Research Proposal” means a brief write-up giving an outline of the proposed research work which the Ph.D. scholar shall submit along with the application for registration for Ph.D. programme;
- v) “University” means a Higher Educational Institution established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act, and shall include any institution for higher education deemed to be a University under Section 3 of the Act.

2.2 Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in Act and not consistent with these Regulations shall have the meanings assigned to them in that Act.

(Clause 2: UGC Ph.D. Regulations 2022)

3. Advertisement, number of seats and commencement of admission

- 3.1. The University shall make a detailed advertisement, including essential qualification, number of seats available for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, list of examination centers, number and specialization of available research supervisors, reservation of seats and last date for submission of the application form etc., for the benefit of the candidates, in at least two national newspapers, of which, at least one shall be in the regional language, as well as on the University website.
- 3.2. The Regional Campuses (RCs) can offer Ph.D. Programme only if they fulfill the condition as per Clause 12 of the UGC Ph.D. Regulations 2022. Based on the recommendations of concerned Departmental Research Committees (henceforth DRCs), the Academic Council (henceforth AC) of the University shall recommend the number of seats to be admitted and advertised in/for various departments of the University and RCs, annually.
- 3.3. Applicants have to make online application in the prescribed format available on the University website (www.igntu.ac.in).
- 3.4. Reservation of the seats for Schedule Castes (SC), Schedule Tribes (ST). Other Backward castes (OBC)-Non-creamy layer, Differently-abled/Divyang, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates shall be as per the Government of India Rules issued from time to time.
- 3.5. The number of seats reserved for SC/ST/OBC/EWS categories may be reduced proportionately if number of qualified candidates is less. The vacant seats reserved for SC/ST/OBC/EWS candidates, if any, shall be filled as per Government of India rules.
- 3.6. Each SC/ST/OBC/EWS candidate shall have to submit a copy of the Caste Certificate issued from the notified person/authority, mentioning that the candidate belongs to SC/ST/OBC (no-creamy layer) community/EWS, as per the Government of India format and rules clearly stating: (a) the name of

candidate and his/her caste/tribe (b) which reserve category s/he belongs (c) District and the State or Union Territory of his/her ordinary residence and (d) the appropriate Government of India Schedule under which his/her caste/tribe is approved. The OBC certificate should clearly mention that the candidate does not belong to creamy layer category.

4. Eligibility criteria for admission to the Ph.D. programme

4.1. The following are eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

4.2. Candidates who have completed:

- 4.2.(i). A 1-year/2-semester master's degree programme after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.
- 4.2.(ii). A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, EWS, and other categories of candidates as per the decision of the Commission (i.e., UGC or its successor)/Government from time to time.
- 4.2.(iii). Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, EWS, and other categories of candidates as per the decision of the Commission (i.e., UGC or its successor)/Government from time to time.
- 4.2.(iv). Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to the Ph.D. programme. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, EWS, and other categories of candidates as per the decision of the Commission (i.e., UGC or its successor)/Government from time to time.

(Clause 3: UGC Ph.D. Regulations 2022).

5. Procedure for admission

5.1. The admission to the Ph.D. programme shall be based on the criteria notified by the IGNTU, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory/regulatory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.

5.2. Admission to the Ph.D. programme shall be made using the following methods:

- 5.2.(i). Students who have qualified for fellowship/scholarship in UGC-NET/UGC- CSIR NET/GATE/CEED/GPAT and similar National level tests based on an interview.

And/or

- 5.2.(ii). Through an Entrance Test conducted by the IGNTU. The Entrance Test syllabus shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject-specific.
- 5.2.(iii). Students who have secured 50% marks in the entrance test are eligible to be called for the interview.
- 5.2.(iv). A relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled, EWS, and other categories of candidates as per the decision of the Commission (i.e., UGC or its successor)/Government from time to time.
- 5.2.(v). IGNTU shall decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available.

- 5.2.(vi). Provided that for the selection of candidates based on the entrance test conducted by the IGNTU, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview/viva- voce shall be given.

The University shall:

- 5.3.(i). Notify a prospectus well in advance on the institution's website specifying the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, the procedure for admission, and all other relevant information for the candidates (also refer to clause 3.1);
- 5.3.(ii). Adhere to the National/State-level reservation policy, as applicable (also refer to clause 3.4 & 3.5).
- 5.3.(iii). IGNTU shall maintain a list of Ph.D. supervisors (specifying the name of the supervisor, his or her designation, and the department/school/centre), along with the details of Ph.D. scholars (specifying the name of the registered Ph.D. scholar, the topic of his/her research and the date of admission) admitted under them on the website of the institution and update this list every academic year.

(Clause 5: UGC Ph.D. Regulations 2022)

6. Classification of the candidates

- 6.1. A candidate admitted to the Ph.D. programme in a department/school/center of the University shall be classified under any one of the following categories:

6.1.(i). Full-time Research Scholar

A candidate who has been admitted to the Ph.D. programme based on the eligibility criteria mentioned in Clauses 4.2.1. - 4.2.4 shall be referred to as a full-time research scholar.

6.1.(ii) Internal Full-time Research Scholar

A candidate who has been admitted to the Ph.D. programme based on the eligibility criteria mentioned in Clauses 4.2.1. - 4.2.4. shall be referred to as an internal full-time research scholar.

a. A regular teacher of the IGNTU and including its Regional Centers be designated as internal candidate. She/He has to produce a No Objection Certificate from the employer. Such candidates will have to avail six-months study leave so as to complete the course work.

b. A non-teaching regular employee of the IGNTU and its Regional Centers be designated as internal candidates. She/He has to produce a No Objection Certificate from the employer. Such candidates will have to avail six-months study leave so as to complete the course work. Such candidates shall have to pass RET for Ph.D. Programme or qualify under exempted category.

6.1.(iii). External Full-time Research Scholar

A candidate working in a non-degree awarding institutions recognized as a center of research by the University through MoUs, and admitted to the Ph.D. programme shall also be permitted to work as an External Full-time Research Scholar, who shall work for his/her Ph.D. in his/her parent organization duly complying with other relevant provisions of these regulations. Such candidates may complete their course work in their parent institutions, if it is at par with the curriculum prescribed by the IGNTU, Amarkantak, otherwise, they have to seek six (06) month study-leave from their parent institutions to attend the course work programme offered by the University. Nevertheless, all candidates admitted under this clause shall have to write course work examinations conducted only by the University.

- 6.1.(iii). In case external full-time research scholars attending their course work classes at their respective institutions, they have to furnish an affidavit from the director/Vice-Chancellor of the institute/organization clearly stating that their course work is at par with the one offered by the University.

6.1.4. Ph.D. through Part-time Mode –

- 6.1.4.(i). Ph.D. programmes through part-time mode will be permitted, provided all the conditions stipulated in these Regulations are fulfilled.

- 6.1.4.(ii). The candidate has to submit a “No Objection Certificate” from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed, clearly stating that:

- The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis.
- His/her official duties permit him/her to devote sufficient time for research.
- If required, he/she will be relieved from the duty to complete the course work.

- 6.1.5** Part time candidate shall have to take six (06) months leave to complete the course work. **(Clause 13: UGC Ph.D. Regulations 2022)**. The eligibility for admission to Ph.D. in part-time mode, in addition to clause 4 is given in Appendix-I.
- 6.1.6.** For admission of International students in Ph.D. Programme the IGNTU may decide their own selection procedure for Ph.D. admission of international students keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by statutory/regulatory bodies concerned from time to time. **(Clause 7: UGC Ph.D. Regulations 2022)**.
- 6.1.7.** On receipt of admission letter, successful candidates shall pay the prescribed fees and complete other formalities pertaining to his/her admission within the stipulated time.
- 6.1.8.** The Head of the Department/Coordinator of the School/ Centre shall send a complete list of the admitted candidates along with the necessary details to the Research cell/Ph.D. section with a copy to the same to the Dean of the Faculty within a week from the date of admission.
- 6.1.9.** No regular Ph.D. scholar shall be allowed to take up any regular paid assignment (except registered under clause 6.1.2 & 6.1.4) during the period of research except Research Fellowships, Research Assistantships/externally funded research project assignments provided it is not detrimental to his/her research programme, as determined by the concerned DRC.

6.1.10. Repealed

- 6.1.11.** All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching /education /pedagogy/writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D. scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations. **(Clause 9: UGC Ph.D. Regulations 2022)**.

7. Research supervisor/co-supervisor & number of permissible Ph.D. scholars

The University shall prepare a list of eligible research supervisors/co-supervisors recommended by the DRCs and subsequently approved by the Research Degree Committee of the University (RDCU).

7.1. Eligibility for Research Supervisor /co-supervisor:

- 7.1.(i).** Permanent faculty members working as Professor/Associate Professor in the IGNTU (including RCs), with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals,
- 7.1.(ii).** Permanent faculty members working as Assistant Professors in the IGNTU (including RCs) with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals be recognized as a Research Supervisor in the University and its RCs. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors.
- 7.1.(iii).** **Repeal:** Only those Assistant Professors of the IGNTU, Amarkantak (including RCs) who have completed their probation period shall be eligible to be appointed as supervisor and co-supervisor.
- Amended:** Eligible permanent faculty members can guide Ph.D. Scholars during their probation period also. **(UGC Notice no. F. 9-1/2020(PS/Misc.) Dated 06/03/2023)**
- 7.1.(iv).** Provided that in areas/disciplines where there is no, or only a limited number of peer-reviewed or refereed journals, the Higher Educational Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.
- 7.1.(v).** For Ph.D. scholars working in Central government/ State government research institutions whose degrees are given by the IGNTU, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/Associate Professor/Assistant Professor can be recognized as supervisors (i.e., external supervisor) if they fulfill the requirements mentioned in the clause 7.1.1 - 7.1.2.

(Clause 6: UGC Ph.D. Regulations 2022)

- 7.1.(vi).** Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can only act as co-supervisors.
- 7.1.(vii).** The university shall endeavor to promote interdisciplinary and cutting edge research. In such research work, if required, a Co-Supervisor from outside the Department/School/ Centre/College/University may be appointed.
- 7.1.(viii).** In case of relocation of a female Ph.D. scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the Higher Educational Institution to which the scholar intends to relocate, provided all the other conditions in these Regulations are followed, and the research work does not pertain to a project sanctioned to the parent Institution/Supervisor by any funding agency. Such scholar

shall, however, give due credit to the parent institution and the supervisor for the part of research already undertaken.

- 7.1.(ix). Faculty members with less than three (03) years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.

(Clause 6: UGC Ph.D. Regulations 2022)

- 7.1(x). Both, internal and external co-supervisor/external supervisor shall be appointed on the request of RAC, and/or approval of the concerned DRC.

- 7.1.(xi) No teacher shall be allowed to supervise/co-supervise his/her blood relatives.

7.2. Allocation of research supervisor and appointment of new supervisor:

- 7.2.(i). The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the concerned DRC depending on the maximum number of scholars per Research Supervisor as specified elsewhere in these regulations, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.
- 7.2.(ii) Keeping the candidate's research interest in view, the concerned DRC shall assign a supervisor, co-supervisor, and external co-supervisor (mandatory, in the case of an external full-time candidate), external supervisor, to supervise the research work of the candidate; shall also notify the Research Advisory Committee constituted as per the related provision(s) of these regulations, to assist the supervisor.
- 7.2.(iii) Co-Supervisors from within the same department or other departments of the same institution or other institutions may be permitted with the approval of the competent authority on the recommendation of the concerned DRC.
- 7.2.(iv) After the allotment of supervisor/co-supervisor, the candidate shall submit an application through his/her RAC to the Head of the Department/Coordinator of the School/Centre informing the proposed topic of research. An external full-time candidate is required to submit the consent of the proposed external co-supervisor/supervisor duly approved by the DRC or equivalent body of that institution along with the above application.
- 7.2.(v) In case where the supervisor of the candidate is appointed in sister or allied departments (as specified in Appendix-II) and co-supervisor in other department of the University, provision for transfer of the candidate (only within a year from the date of registration) pursuing research under his/her supervision in the previous department shall be available provided the candidate opts for it and the DRC of the concerned department agreed to the proposed transfer. However, the research scholar, subsequent upon transfer, shall be governed by the rules of the department/faculty to which he/she is transferred.
- 7.2.(vi) If the supervisor of a candidate proceeds on leave/lien/deputation for a period of more than 12 months, she/he shall request the concerned DRC to appoint a co-supervisor for the student.
- 7.2.(vii) However, if a supervisor proceeds on a leave/lien/deputation for a period more than 12 months or for a period of less than 12 months, but later extends his/her leave/lien/deputation beyond 12 months, and there is no co-supervisor for the student, then, she/he shall cease to be the supervisor. The concern DRC will appoint a new supervisor for the student.
- 7.2.(viii) If the supervisor of a candidate expires or is terminated from the University service, she/he shall cease to be the supervisor. In such case the concerned DRC shall appoint a new supervisor.
- 7.2.(ix) In all the cases, where the existing supervisor of a candidate ceases to be the supervisor, the DRC shall appoint a new supervisor. Or, if the candidate is having a co-supervisor in other department of the University, the candidate may opt for his/her transfer to that department, and she/he may be allowed to do so, on mutual consent of both the DRCs.
- 7.2.(x). In case of any ambiguity chairperson of the concerned DRC shall act as supervisor till the appointment of new supervisor by the DRC. Such supervision shall be treated as temporary or transitory in nature. However, if there are not enough eligible teachers in the department, or any other cogent reasons, if the Chairperson of the DRC continue his/her supervisory duties for more than a year, she/he shall *suo moto* be designated as supervisor of the student.
- 7.2.(xi) In case of serious complaint/allegation in writing by the research scholar against the supervisor involving sexual harassment/exploitation, such cases shall be dealt strictly as per the provision of UGC (prevention prohibition and redressal of sexual harassment of woman employees and students in HEIs) Regulations, 2015 and subsequent amendments to it. However, in such cases during the period of enquiry the concerned Head of

the Department/Center/School shall act as interim supervisor. It shall be incumbent upon the University to complete such enquiry within six (06) of the date complaint was received. In case allegation stands validated the concerned DRC shall appoint a new supervisor for the student. Otherwise, the scholar shall revert to the original supervisor. Further, necessary action should be taken against such scholar including cancellation of his/her registration.

7.2. (xii) In case the supervisor proceeds on lien/deputation and wishes to transfer his/her student to the new institution, it is permissible only within one year from the date of registration (first fee payment date) of the candidate.

7.2. (xiii) In case the supervisor proceeds a transfer to other department in IGNTU by reappointment, the scholar remain in the same department where the scholar registered. In such case, the concerned DRC shall appoint a new supervisor to the scholar and the previous supervisor remain as co-supervisor. No interdepartmental transfer of scholar shall be allowed.

7.3. Number of research students under a research supervisor/co-supervisor

7.3.(i). A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, Associate Professor, and Assistant Professor, at any given point of time, can supervise maximally eight (08), six (06), and four (04) Ph.D. scholars, respectively.

7.3.(ii). The number of Ph.D. scholars working under a co-supervisor shall also be counted in his/her permissible quota of students.

7.3.(iii). In case of International students each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars as specified in the clause 7.3.1.

(Clause 6, 7 and 8: UGC Ph.D. Regulations 2022)

7.4. Inter-disciplinary Research

7.4.(i). A candidate may be permitted or encouraged to do inter-disciplinary research. She/he may be permitted for admission/registration in a department/school/ faculty other than that in which she/he has obtained his/her Master's degree, depending upon the nature of his/her research problem and subject to the recommendation of the concerned DRC.

7.4.(ii). Application for research in inter-disciplinary area shall be considered on the basis of proven ability and aptitude of the candidate for such kind of work.

7.4.(iii). To serve this purpose, the University shall develop a list of such teacher with expertise in interface subject as supervisor/co-supervisor.

8. Duration of the programme

8.1. Ph.D. programme shall be for a minimum duration of three (03) years, including course work, and a maximum period of six (06) years from the date of admission to the Ph.D. programme.

8.2. A maximum of an additional two (02) years can be given through a process of re-registration; provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (08) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

8.3. Provided further that, female Ph.D. scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation of two (02) years; however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

8.4. Female Ph.D. Scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave for up to 240 days in the entire duration of the Ph.D. programme.

(Clause 4: UGC Ph.D. Regulations 2022)

8.5. If a candidate fails to submit the thesis at the end of the stipulated period (03 year), the concerned DRC, may grant an extension of up to three years (03), one year at a time, for the submission of the thesis, on the request of the concerned Research Advisory Committee (RAC), such that the total period for the submission of the thesis counted from the date of his/her admission does not exceed six (06) years. However, the University shall not provide fellowship to such scholar for the extension period beyond whatever is decided in the Academic Council of the University.

8.6. After the expiry of six (06) years period, the candidate has to re-register himself, for which the candidate shall apply giving the reasons due to which she/he could not submit the thesis. Such application shall be duly forwarded and recommended by the concerned RAC and DRC. Once re-registration has been accepted, the candidate may submit his/her thesis anytime within two (02) years.

8.7. The criteria of minimum submission period (03 years) shall not be applicable in re-registration cases.

9. Course work

- 9.1. The course work is a prerequisite for Ph.D. submission.
- 9.2. The course work shall be for a minimum period of one semester. All the enrolled Ph.D. candidates (henceforth referred to as Ph.D. scholar or, Scholar) shall have to qualify the course work as per the criteria prescribed by the concerned department/faculty/University.
- 9.3. All the scholars admitted to the Ph.D. programme shall be required to complete the prescribed course work during the initial two semesters.
- 9.4. In case a Ph.D. scholar fails or not appeared in the examination due to cogent reason in the course work examination, she/he shall be given one more chance to clear the examination. However, if she/he fails again his/her admission shall stand cancelled.
- 9.5. The credit assigned to the Ph.D. program shall be a minimum of 12 credits, including a “Research and Publication Ethics” course as notified by UGC vide D.O. No. F.1-1/2018(Journal/CARE) in 2019 and a research methodology course. The Research Advisory Committee can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the Ph.D. programme. **(Clause 9: UGC Ph.D. Regulations 2022).**
- 9.6. A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 10-point scale in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis. **(Clause 9: UGC Ph.D. Regulations 2022).**
- 9.7. The details of the courses, course credits, passing criteria and other related matters decided by the University must be in conformity with the then applicable UGC Regulations.
- 9.8. All courses prescribed for Ph.D. shall be duly approved by the concerned Board of Studies/Faculty Board). Such courses may be from the same faculty/department where the scholar is enrolled or from other faculties depending upon the nature of research area.
- 9.9. After completing the course work, the scholar shall appear in a comprehensive examination, the modality of conduct of which shall be decided by the concerned department/faculty or at the University level.
- 9.10. Only those scholars whose attendance are 75% or above during the course work period shall be allowed to appear in the examinations. The concerned department will verify the attendance. In case of external full-time research scholars, the Head of the concerned institutions shall provide a certified copy of attendance to the Head of the department where candidate is enrolled, who shall forward the same to the office of the Controller of Examinations, IGNTU, Amarkantak.
- 9.11. All the enrolled scholars shall submit their first progress report to the Research/Ph.D. section through his/her RAC duly forwarded by the concerned DRC.

10. Research proposal Submission and Registration of candidates for the Ph.D. period

- 10.1. Once a candidate deposit his/her first fee, she/he shall be deemed to be provisionally registered to the programme. The date of registration shall be the date of the submission of first admission fee.
- 10.2. Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed in clause (3) of Regulation 9 above, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022)**
- 10.3. Within a month of successfully completing the course work, a scholar shall have to submit synopsis/research plan proposal on the proposed research work including title of the research work to the DRC through RAC in prescribed format.
- 10.4. The DRC shall examine the research plan proposal of the candidate including a presentation by the candidate. The DRC shall invite one external subject expert, who is not in the service of this University for evaluation of in the “Research Plan Proposal and Seminar”.
- 10.5. The DRC shall submit a panel of at least three names of external experts not below the rank of university Professor for the approval of the Competent Authority. The approved name shall remain valid for one year from the date of its notification.
- 10.6. The DRC on its satisfaction to the research proposal shall approve the proposal and the topic of the research. If any correction/change/improvement is suggested by the DRC, the candidate shall have to incorporate the same and resubmit to the DRC, with an assurance from the supervisor that changes have been incorporated.

- 10.7. If the DRC is not satisfied with the quality of the research plan proposal, the candidate shall submit a fresh proposal and deliver the seminar within a time limit specified by the DRC (not exceeding one month in any case), and a fresh evaluation shall be done. But, if only the seminar is unsatisfactory, the candidate shall deliver only the seminar again within one month.
- 10.8. If a candidate fails to submit the research plan proposal within the time specified above his/her candidature shall stand cancelled. After the conclusion of Research Plan Proposal Seminar the scholar has to submit a synopsis on the approved topic through the RAC to the DRC.
- 10.9. The DRC shall forward its recommendation on the synopsis to the Research/Ph.D. section. The section shall forward the synopsis to the RDCU for approval.
- 10.10. The notification of RDCU approval must be communicated by the office of the Registrar of the University to the concerned department, supervisor and the scholar within a month of the date of receipt of the DRC minutes/recommendations (Research Plan Proposal approval minutes).

11. Attendance Requirements

- 11.1. A Ph.D. scholar is required to sign on all working days of the University in an attendance register to be kept in the office of the concerned Head of the Department/Coordinator of the School/Centre, except when she/he is on duty/sanctioned leave approved by the DRC and/or the RDCU.
- 11.2. The attendance requirements and leave rules shall be applicable to the external full-time research scholars and she/he shall submit a statement on requisite attendance from the center where she/he is pursuing his/her research through his/her co-supervisor (except in case of Course Work), to the concerned Head of the Department.

12. Residency Period

- 12.1. A full time Ph.D. Scholar shall be required to be compulsorily present in the University for a period of two years, which is known as the Residency Period (i.e., the duration she/he cannot take any regular paid assignment), in a single stretch except in case of maternity/childcare leaves.
- 12.2. For internal full-time research scholar described in clauses 6.4.2. and part-time Ph.D. scholars described in the clause 6.4.4. & 6.4.5., the residency period shall be the minimum period required for completing the course work (i.e., six month).

13. Leave Rules

- 13.1. A Ph.D. scholar shall be eligible to avail a leave of 30 days in a calendar year. She/he shall not be entitled for any inter-semester breaks, winter and summer vacations. However, she/he is entitled for an additional leave of up to 10 days on medical grounds in a calendar year. The aforesaid leave provisions are cumulative.
- 13.2. Male/female scholars shall be eligible for paternity/maternity/childcare leaves as per University/UGC rules once during their entire tenure as research scholar.
- 13.3. The leave mentioned in the clause 13.1. shall be granted by the Head of the Department/Coordinator of the School/Centre on the recommendation of the supervisor/co-supervisor. However, the maternity and child care leaves mentioned in the clause 13.2 shall be approved the RDC on the recommendation of the concerned DRC.

14. Duty or study leaves

- 14.1. If a Ph.D. scholar is willing to proceed for data collection/field trip for or less than two (02) weeks period, she/he may do so on the recommendation of the concerned RAC, duly intimated to the concerned Head of the department/ Coordinator of the School/Center.
- 14.2. The DRC may recommend a Ph.D. scholar to pursue a part of his/her research work at a place outside the University (including abroad), for a period of 60 days. However, if such recommendations are for a period beyond 60 days, the recommendations of the DRC would be placed before the RDCU, which may permit a Ph.D. scholar to pursue a part of his/her research work at a place outside the University (including abroad) without exceeding the maximum time limit for the submission of the thesis laid down in these regulations.

15. Financial assistance

- 15.1. Subject to the availability of funds from the UGC or its successor/other funding agencies, the Ph.D. scholars admitted as full time scholar would be entitled to the scholarship/fellowship (including contingency grant) of such amount as prescribed by the funding agencies (e.g., The University

Research Fellowship that is being provided by the UGC, New Delhi) from time to time. The award of scholarship/fellowship shall be subject to the fulfillment of the conditions governing such award.

- 15.2. The maximum duration of the UGC-University Research Fellowship is of three years, subject to satisfactory research performance of the scholar, on semester basis, and submission of a semester-wise continuation certificate from the supervisor.

One additional year of the above fellowship may be granted to the enrolled scholars subject to the production of extension letter from the concerned DRC and availability of funds from the UGC. In case of candidate having their own fellowship from different funding agencies, the terms and conditions of the funding agency shall be applicable on such scholars.

16. Pre-submission of Thesis

- 16.1. Prior to the submission of the thesis, the scholar has to submit at least six half-yearly progress reports to the office of the Research Cell/Section.
- 16.2. The respective RAC and DRC shall monitor the academic/research progress of each scholar. For this purpose, the candidate shall submit a progress report on a prescribed proforma in triplicate, at the end of each semester to the RAC through his/her supervisor and co-supervisor, if any.
- 16.3. The scholar shall also present the progress of his/her research work through a seminar to the RAC, who shall evaluate the progress made by the candidate and submit its recommendations to the concerned DRC.
- 16.4. The Chairperson of the DRC shall forward the progress report with specific recommendations to the Research Cell/Section through the Dean of the faculty.
- 16.5. Progress of a scholar in any semester shall be deemed to be unsatisfactory if the she/he is absent for a period more than that specified in these regulations.
- 16.6. The Ph.D. scholar shall submit progress reports for each semester till the submission of the thesis. The last progress report of the scholar shall be submitted to Research Cell/Section, in the manner prescribed above, three days prior to of the submission of thesis.
- 16.7. Before submitting the dissertation/thesis, the Ph.D. scholar shall make a presentation before the RAC/DRC of the department concerned, which shall also be open to all faculty members and other research scholars/students. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022).** The supervisor shall organize a pre-submission seminar (not before the minimum required period for submission of the thesis i.e., 03 years), in consultation with the Head of the Department/Coordinator of the School/Centre, to apprise the teachers and other researchers of the Department/School/Centre of the scholar's work and receive suggestions for improvement of the research work. The RAC and the DRC shall assess the work of the candidate through this seminar. The seminar will be held in the department and shall be open for all. The suggestion so emerged may suitably be incorporated into the draft thesis.
- 16.8. If the RAC and/or the DRC are not satisfied with the quality of the work of the scholar, then she/he shall do further work and deliver a fresh seminar after a definite period specified by the DRC.
- 16.9. If the DRC is satisfied with the pre-submission seminar of the scholar, the Chairperson of the DRC shall forward the application of the scholar for submission of the thesis along with a certificate about the satisfactory completion of the pre-submission seminar and the exact title of the thesis to the Controller of Examinations with a copy of the same to the Dean of the faculty. Any extended residency period left beyond the date on which the thesis is forwarded for submission shall be deemed to have been terminated on the said date.
- 16.10. The exact title of the thesis shall be as approved by the DRC after the pre-submission seminar.

17. Change in the Research Topic

- 17.1. No major change in research topic shall be accepted after registration (at the time of synopsis submission). However, if candidate and his/her supervisor are of the opinion that minor changes are necessary, they may report the case in the concerned DRC, upon approval, this should be notified to the office of Controller of Examinations. Such changes are to be permitted for only once, before or after pre-submission seminar by the scholar.

18. Language of the thesis

- 18.1. The language of the thesis shall either be in English or Hindi, except for the thesis submitted in the area of languages.
- 18.2. In case language of the thesis is other than English, the scholar has to submit one page summary of the work in English.

19. Unfair means and plagiarism

- 19.1. In case a Ph.D. scholar is found adopting or suspected of adopting unfair means or lifting of other's work and inserting it in his/her work without proper acknowledgement, credit and reference. The university may take such penal action as may be necessary to uphold the sanctity and the integrity of the research work and the credibility of the university.
- 19.2. The thesis must comply with the UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018.
- 19.3. The University may take *suo-moto* cognizance of all such unethical practices/cases. Such cases may also be reported by any person to the University through the Head of the Department/Coordinator of the School/Dean of the faculty.
- 19.4. For works involving animals, transgenic alien seeds, explants and hazards materials must comply with guidelines of animal ethics and bio-safety recommendations issued from time to time by the UGC and other concerned agencies.
- 19.5. The University shall have a mechanism using well-developed software applications to detect Plagiarism in research work and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a Ph.D. degree (as envisioned in the UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018). **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022)**
- 19.6. A Ph.D. scholar shall submit the thesis for evaluation, along with (a) an undertaking from the Ph.D. scholar that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/diploma to any other Higher Educational Institution. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022)**

20. Submission of Thesis

- 20.1. The scholar is required to submit the thesis within six months from the date of his/her pre-submission seminar (without exceeding the maximum time limit for the submission of the thesis as laid down elsewhere in these regulations), failing which he/she shall be required to deliver a fresh pre-submission seminar.
- 20.2. One month prior to submission of the thesis the candidate has to submit six (06) copies of the summary/abstract of the thesis, duly forwarded by Head of the concerned Department/Coordinator of the School/Centers, describing the salient features of his/her work, to the office of Controller of Examinations/Ph.D. Section.
- 20.3. The scholar is required to submit one (01) soft copy of the thesis on CD/Pen Drive in non-editable/Secure PDF format along with the hard copies of the same.
- 20.4. The scholar shall submit six (06) hardbound printed copies of the thesis to the office of the Controller of Examinations, duly forwarded by the Head of the Department/Coordinator of the School/Center. The thesis shall contain the certificate by the supervisor in prescribed proforma, a declaration by the candidate in prescribed proforma, a course work completion certificate, pre-submission seminar completion certificate, and a copyright transfer certificate in prescribed proforma, anti-plagiarism statement and other necessary certificates, as required from time to time.
- 20.5. The model for cover and title page of the thesis has been appended as Appendix-XIV and Annexure II to these regulations and shall be strictly followed.
- 20.6. The thesis must be a piece of original research work characterized by the discovery of facts or by fresh approach towards the interpretation of facts or theories on an applied work of great significance. In either case it shall evince the capacity of the scholar for critical examinations and independent judgment, and should also be satisfactory as far as literary presentation is concerned.
- 20.7. A thesis once submitted cannot be re-submitted except when the examiner recommends for the revision of the thesis.

21. Evaluation and Assessment procedure:

- 21.1. The supervisor through concerned DRC shall submit a panel of six (06) external experts in the concerned subject representing different parts of the country, of which, not more than two (02) should be from the single state, but not more than one from a single university, in prescribed format to the office of the Controller of Examinations. Wherever possible, one of the external examiners should be chosen from the outside India. The external examiner(s) should be academics with a good record of scholarly publications

in the field. The Vice-Chancellor may however ask for more names of experts. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022)**

- 21.2. The external expert panel shall include the names of Professor (or equivalent), however, a maximum of one name not be below the rank of Associate Professor (or equivalent) may be allowed.
- 21.3. The Research supervisor/co-supervisor has to ensure that suggested examiners must not be in blood relation with the Ph.D. scholars as well as Research Supervisor.
- 21.4. The examiner panel must not contain any name from the institution of scholar's supervisor and co-supervisor.
- 21.5. In the case of a research scholar who has done any part of his/her work in another institution, the panel of examiners shall not include any person working in that institution.
- 21.6. In case the subject of research area is such that adequate numbers of experts are not available within the country; the panel may contain names of experts from foreign countries.
- 21.7. The concerned supervisor shall act as internal examiner.
- 21.8. The Vice-Chancellor would then select and appoint two (02) names from the panel as external examiners. The names shall be communicated to the office of the Controller of Examination.
- 21.9. The Controller of Examinations shall get in touch with each examiner with a copy of the summary/abstract to secure acceptance of the examinership. For this purpose, if e- mail address of the examiner is available, she/he shall be contacted through e-mail to get his/her consent at the earliest. If however, no information is received from an examiner within two-week period from first communication to the examiner. After this a reminder will be given to examiner, if no response is received within two-weeks from the date of reminder, his/her appointment shall be cancelled and the Vice-Chancellor shall appoint a new examiner from the existing panel of examiners.
- 21.10. The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor (internal examiner) and at least two external examiners (selected by the Vice-Chancellor), who are not in employment of the University. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022)**
- 21.11. Examiners shall have to send their reports in specified proforma.
- 21.12. The viva-voce of the Ph.D. scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them. If one of the external examiners recommends rejection, the University shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners, and the viva-voce examination shall be held only if the alternate examiner recommends acceptance of the thesis. If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected, and the Ph.D. scholar shall be declared ineligible for the award of a Ph.D. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022).**
- 21.13. In case one examiner accepts and another suggests for major revision, concerned DRC shall inform student and his supervisor to incorporate necessary changes to the satisfaction of DRC. If the external examiner has requested to resend the thesis to him after revisions, the same shall be forwarded to the examiner.
- 21.14. The University shall complete the entire process of evaluating a Ph. D. thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022).**
- 21.15. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the viva voce board. The viva-voce board shall consist of the Research Supervisor and at least one of the two external examiners and may be conducted online. The viva-voce shall be open to the members of the Research Advisory Committee/ concerned Head of the department/Coordinator of the School/Centers/ faculty members/research scholars, students and other interested experts/researchers. **(Clause 11: UGC Ph.D. Regulations 2022)**

22. Award of the Degree

- 22.1. In general, the Ph.D. degree shall be awarded in the subject/department where the candidate is enrolled on the topic chosen and approved by the DRC.
- 22.2. The date of award of degree shall be the date of submission of the thesis to the University. However, in case of revision the date of submission shall be the date of submission of revised thesis.
- 22.3. Once submitted, the office of the Controller of Examinations shall issue a submission certificate to the scholar.

- 22.4. The University shall complete the entire process of evaluating a Ph.D. thesis, including the declaration of viva-voce result, within a period of six months from the date of submission of the thesis.

23. Issuing a Provisional certificate

- 23.1. The actual degree shall be awarded in convocation convened by the University from time to time.
- 23.2. Prior to the actual award of the degree, the University shall issue a provisional certificate to this effect to the scholar that the Ph.D. is being awarded in accordance with the provisions of IGNTU Ph.D. Regulations 2016/2022. **(Clause 15: UGC Ph.D. Regulations 2022).**

24. Cancellation of Registration

The registration of a Ph.D. scholar shall be cancelled by the DRC in any one of the following eventualities:

- 24.1. If a scholar fails to submit satisfactory progress report through supervisor regularly for two years (i.e., four half-yearly progress report).
- 24.2. If a scholar is absent for a continuous period of four weeks without prior information/sanction of leave.
- 24.3. If a scholar fails to submit synopsis within stipulated time.
- 24.4. If a scholar fails to renew his/her registration in any semester subject to the provisions contained in these regulations.
- 24.5. If a scholar fails to submit the thesis within the maximum stipulated time as provided in these regulations.
- 24.6. If a scholar resigns from the Ph.D. programme and the resignation is duly recommended by his/her research supervisor.
- 24.7. If a scholar is found involved in an act of misconduct and/or indiscipline and the Competent Authority has recommended his/her termination.
- 24.8. If a scholar fails to deposit the fee within the prescribed time.

25. Temporary withdrawal from the programme (De-registration and Re- registration)

- 25.1. A scholar admitted to the Ph.D. programme may be permitted by the RDCU, on recommendation of the DRC to temporarily withdraw from the programme on some specific reasons (termed as 'de-registration'), and later allowed to join back to complete the research (termed as 're-registration') and submit the thesis, without exceeding the maximum prescribed time limit for the thesis submission as described elsewhere in these regulations. This withdrawal may be granted for whole or part of the semesters. The relaxation shall be provided only once in entire tenure of Ph.D. research. The temporary withdrawal may be permitted on any one of the following reasons:
- 25.1.(i). If the candidate gets a professional employment, and has completed the residency period.
- 25.1.(ii). If a fulltime sponsored candidate after fulfilling the minimum residency period requirement for the submission of the thesis joins back his/her parent organization.
- 25.2. Except in case of maternity leave, the above relaxation shall only be availed after completion of the minimum residency period.
- 25.3. During the period of withdrawal the candidate has to pay fee, and submit progress reports timely.

26. Depository with INFLIBNET

Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree, the University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions. **(Clause 7: UGC Ph.D. Regulations 2022).**

27. Research Committees

Subject to the general superintendence of the Academic Council, the following Committees shall deal with all matters related to the Ph.D. programme of the University in accordance with these regulations:

- 1) The Research Degree Committee of the University (RDCU)
- 2) The Departmental/School/Centre Research Committee (DRC)
- 3) The Research Advisory Committee (RAC)

- 27.1. The RDCU shall consist of the following (as per section 2 of the ordinance 46 of the University):

i)	Vice-Chancellor /Pro-Vice Chancellor (ex-officio)	Chairperson
ii)	Dean of the Faculty (ex-officio)	Member
iii)	Head of Departments of the University/Regional Campuses/ Centers not exceeding five by rotation	Member
iv)	Professors other than dean of the faculty and Head of the Departments not exceeding five by rotation	Member
v)	Four Associate Professors to be nominated by the Vice- Chancellor representing different disciplines in the University/Regional Campuses/ Centers	Member
vi)	Four external experts to be nominated by the Vice-chancellor representing different discipline in the University	Member
vii)	Registrar	Secretary (Ex-officio)

Registrar shall convene the meetings of the RDCU, at least twice in a calendar year.

The functions of RDCU shall be as mentioned in section 2 of the Ordinance 46 of the University. The quorum of the RDCU shall be 1/3 of the total members.

The term of office of the member other than ex-officio member shall be for a period of three years.

27.2. The DRC shall consist of the following:

i)	Head of the Department	Chairperson
ii)	All Professors in the Department	Member
iii)	One Associate Professor of the Department, according to seniority, by rotation every three years	Member
iv)	One Assistant professor of the Department, according to seniority, by rotation every three years	Members
v)	Supervisor and Co-Supervisor (if any) of the concerned Ph.D. scholar	Member (s)
vi)	One external expert not below the rank of Professor*	Member

In case there are three or less than three eligible teachers in the Department/School/Center, the DRC shall consist of the following:

i)	The Dean of the concerned faculty	Chairperson
ii)	All eligible teachers of the Department	Members
iii)	A senior teacher of a sister Department nominated by the Dean in consultation with the Head of the Department	Member
iv)	One external expert not below the rank of Professor*	Member

* Only at the time of synopsis presentation/research plan proposal seminar and the nomination valid for one (01) year.

The DRC shall appoint one of its members by rotation as Secretary or Convener.

27.3. The RAC shall consist of the following:

There shall be a Research Advisory Committee for each Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the Ph.D. scholar concerned shall be the Convener of this committee, and this committee shall have the following responsibilities:

27.3.4. To review the research proposal and finalize the topic of research.

27.3.5. To guide the Ph.D. scholar in developing the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

27.3.6. To periodically review and assist in the progress of the research work of the Ph.D. scholar.

(2) Each semester, a Ph.D. scholar shall appear before the RAC to make a presentation and submit a brief report on the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The RAC shall submit its recommendations along with a copy of Ph.D. scholar's progress report to the Higher Educational Institution concerned. A copy of such recommendations shall also be provided to the Ph.D. scholar.

(3) In case the progress of the Ph.D. scholar is unsatisfactory, the RAC shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Ph.D. scholar fails to implement these corrective measures, the RAC may recommend, with specific reasons, the cancellation of the registration of the Ph.D. scholar from the Ph.D. programme.

(Clause 10: UGC Ph.D. Regulations 2022).

i)	Internal Supervisor of the concerned Ph.D. Scholar	Convener
ii)	Co-supervisor/external supervisor (if any) of the concerned Ph.D. Scholar	Member
iii)	A nominee of the Chairman of DRC	Member
iv)	A member from the sister/allied subject/department on the recommendation of the Supervisor.	Member

A teacher who is not eligible to guide a Ph.D. scholar cannot become a member of any of the research committees mentioned above.

The DRC shall not make any recommendation that is not in conformity with these regulations.

28. Difficulty: Notwithstanding anything contained in these Regulations, any question, which is not covered by these Regulations, or any difficulty arising out of these Regulations, shall be dealt with by the Academic Council.

29. Repeal: From the date when Ph.D. Regulations comes into force all previous regulations on the subject shall cease to have effect. Provided that this revocation shall not affect the previous regulations so revoked or anything done or suffered under any previous regulations so revoked or affects any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any regulations so revoked.

30. Fee structure: As notified by the University from time to time.

Prof. N.S.H.N. MOORTHY, Registrar (i/c)

[ADVT.-III/4/Exty./718/2023-24]

Appendix-I

Provisions for Part-Time Ph.D.

1. Eligibility for Part-time Research Scholars

- a. A permanent/regular teaching faculty of any Higher Education Institution (HEI), provided s/he justifies the need for a such degree and duly endorsed by the parent institution, clearly stating that the faculty shall be permitted for leaves as per need of the program.
- b. A permanent government servant, not below the rank of the group 'B' services (as defined by the DoPT), provided s/he justifies the need for such a degree and his/her application is duly endorsed by the parent institution, clearly stating that the employee shall be permitted leave as per need of the program.
- c. Candidates from industries/Corporate sector:
 - i. The Industry/Corporate sector should have been duly approved by the concerned Regulatory Body e.g., FSSAI, ICAR, GMP, etc.
 - ii. The candidate should have completed a minimum of five years of permanent/regular service in the same organization, not below the rank of group 'B' government services.
 - iii. Justification for the need for such a degree in organizational/societal advancement.
 - iv. Till completion of the Ph.D., the candidate has to work in the same organization, if s/he leaves the organization during the program, her/his admission shall be canceled.
 - v. Any IPR arising out of the work shall be the sole proprietary of the IGNTU.

Criterion for Journalism and Mass Communication

- i. Three years of working experience as sub-editor/staff reporter/ correspondent or senior editorial position in ABC accredited newspapers or experience of journalism of the above mentioned or equivalent capacity from digital editions/news portals of the ABC accredited newspapers. The newspaper/digital editions/news portals must have been uninterruptedly and regularly under publication for a period of not less than thirty-six (36) months. Experience from House periodicals, souvenirs, annual periodicals, bi-monthlies, quarterlies, social media sites, non-recognized portals and second edition of any periodical will not be considered.
 - ii. Three years of working experience as editorial crew/staff reporter or senior editorial position in ABC satellite news channels. The news channel must have been uninterruptedly and regularly under operation and on air for a period of not less than thirty-six (36) months. Experience from House periodicals, souvenirs, annual periodicals, bi-monthlies, quarterlies and second edition of any periodical will not be considered.
 - iii. Three years of working experience as content editor/presenter/ announcer or anchor, or senior position in creative section in recognized Radio station. The Radio station must be operational and available for listeners for a period of not less than thirty-six (36) months.
 - iv. Three years of working experience in any central government or state government media organization/ government organization/PSUs/ Autonomous bodies as not less than class B employee.
 - v. Three years of working experience in creative section of advertising/PR agency accredited by INS or similar body/Central Bureau of Communication. The agency must be in operation for a period of not less than thirty-six (36) months.
 - vi. A recognized film/documentary film maker with evidence of certification and release/ public exhibition of at least one film/documentary film produced/directed/ contributed as creative member.
 - vii. Justification for the need for such a degree in organizational/societal advancement.
 - viii. Till completion of the Ph.D., the candidate has to work in the same organization, if s/he leaves the organization during the program, her/his admission shall be canceled.
 - ix. Any IPR arising out of the work shall be the sole proprietary of the IGNTU
2. The admission of Part-Time candidates shall be governed by the then-applicable UGC and IGNTU regulations e.g., UGC Ph.D. Regulations 2022 and IGNTU Ph.D. Regulations 2023. That is -
 - a. Admission to such candidates shall be only through the Research Entrance Test (RET) or exempted category as specified in the regulations. No direct admission or any specific quota.
 - b. It is mandatory for such candidates to avail of six months' leave to complete the requisite coursework
 - c. S/he shall not be entitled to any fellowship/scholarship from the University.
 3. In addition to the above-mentioned documents, the candidate has to submit a "No Objection Certificate" from the Appropriate Authority of her/his parent organization, clearly stating that:
 - a. The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis.
 - b. His/her official duties permit him/her to devote sufficient time to research.
 - c. If required, he/she shall be permitted leave and be relieved from the duties as and when asked for.

Appendix –II

A list of departments and their allied or sister subjects (the list is non-exhaustive and purely for enrollment in University Ph.D. programme, not for employment purpose).

Sl. No.	Name of the Department	Allied/sister subject(s)
1	Botany	Plant Science, Biological Science (with specialization in Plant Science, Life Science (with specialization in Plant Science), Environmental Science, Biotechnology (with Specialization in Plant Science), Genetics, Bioinformatics, Biochemistry, Agriculture, Food Science, Microbiology.

2	Biotechnology	Botany, Zoology, Microbiology, Animal Science, Biological Science, Life Science, Environmental Science, Agriculture Science, M.Tech. in Biotechnology, M. Tech. in Biological Sciences, Medical Sciences, Engineering Sciences, Chemical Sciences and Physical Sciences, Genetics, Biochemistry
3	Chemistry	Biochemistry, Material Science, Industrial Chemistry
4	Environmental Science	Botany, Zoology, Animal Science, Biological Science, Life Science, Geology, Sociology, Economics, Agriculture, Chemistry/Chemical Science.
5	Geology	Environmental Science, M.Tech. in Civil Engineering, Mining and Metallurgy
6	Mathematics	Cosmology
7	Physics	Cosmology, Material Science, Condensed Matter Physics, Quantum Physics, Spectroscopy, Nuclear Physics
8	Statistics	Mathematics, Computer Science, Population Studies, Agricultural Statistics, Health Statistics, Data Science, Demography and Biostatistics
9	Zoology	Animal Science, Biological Science (with specialization in Animal Science), Life Science (with specialization in Animal Science), Biochemistry, Neuroscience, Genetics, Food Science, Bioinformatics, Biotechnology (with specialization in Animal Sciences), Fishery, Entomology